समसामयिकी

जनवरी - 2019

www.IASbook.com

IASbook

EDITOR'S NOTE

IASbook करेण्ट अफेयर्स दिन-प्रतिदिन प्रस्तुत करते समय हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि करेण्ट अफेयर्स के वही टॉपिक चुने जाएं जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हों और इसमें अनर्गल एवं गैर जरूरी तथ्यों को समावेशित कर आपके पढ़ने का भार न बढ़ाया जाए।

दूसरा यह ध्यान रखा गया है कि इस प्रकार की सामग्री के प्रति आपके विश्वसनीयता के संकट को दूर किया जा सके। करेण्ट अफेयर्स से संबंधित सूचनाओं को तुरंत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा किंतु तथ्यों की प्रामाणिकता को समय पर तरजीह दी गयी है।

पाठकों की संतुष्टि हमारे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि अपने फीडबैक से हमें अवश्य अवगत कराएं। आपकी आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। इससे हमें आगामी दिनों में सामग्री के स्तर में सुधार की दिशा प्राप्त होगी। आशा है कि करेन्ट अफेयर्स का पीडीएफ (जनवरी,2019) पाठकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

-

Team IASbook

www.iasbook.com

"

हमेशा ध्यान में रखिये की आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्त्वपूर्ण है

-अब्राहम लिंकन

राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance)

1. 9वाँ मतदाता दिवस
2. कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)
3. वोटर हेल्पलाईन एप, 'पीडब्ल्यूडी एप' और VVIP कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)
5. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 (National Youth Parliament Festival 2019)
6. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations)

1. अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) का आह्वान
2. भारत-रूस संबंध
3. भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास-2019
4. 15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस
5. आसियान-भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक
6. भारत सबसे भरोसेमंद देशों में से एक
7. भारत सरकार और JICA के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
8. भारत ने जर्मनी और स्वीडन के साथ रक्षा समझौतों पर किये हस्ताक्षर
9. सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली
10. सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली
11. राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण
12. नो इंडिया प्रोग्राम (Know India Programm)

अर्थव्यवस्था (Economy)

1. रत्न और आभूषण के लिये घरेलू परिषद
2. अटल सेतु (Atal Setu)
3. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश
4. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक - 2019
5. केरियन गंडियाल पुल (Kerrian Gandyal bridge)
6. वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन (Vibrant Gujarat Summit)
7. कुसुम योजना (KUSUM Scheme)
8. सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति-पत्र
9. 'राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस' (National Productivity Day)
10. एक्वा मेगा फूड पार्क (Aqua Mega Food Park)
11. देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र
12. 'लाइट हाउस परियोजना चुनौती' (Light House Project Challenge)
13. मोबाइल-एप ई-कोकून
14. पेट्रोटेक- 2019
15. देश की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग
16. वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
17. ओवरड्राफ्ट (Overdraft)
18. देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज (Country's Longest Single Lane Steel Cable Bridge)
19. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (Electronic National Agriculture Market e-NAM)
20. फ्रिंज बेनिफिट (Fringe Benefit)
21. कड़कनाथ मुर्गा
22. एकल खिड़की हब 'परिवेश'
23. पांडा बॉण्ड (Panda Bond)
24. प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana)
25. 'वन फैमिली, वन जॉब' योजना ('One Family, One Job' Scheme)
26. श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना की शुरुआत
27. उज्ज्वला उत्सव
28. पोलावरम परियोजना

पर्यावरण (Environment)

1. पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) कोष
2. बायो-जेट ईंधन के लिये नया मानक
3. काजीरंगा के दो गैंडों को मिला नया घर
4. उभयचरों की 19 प्रजातियाँ गंभीर रूप से लुप्तप्राय
5. फ्लेमिंगो महोत्सव (Flamingo Festival)
6. 'सक्षम 2019' (Saksham 2019)
7. 687 परियोजनाओं में से 682 को मंज़ूरी
8. तीसरा भारत- जर्मन पर्यावरण सम्मेलन
9. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य
10. चक्रवात 'पाबुक'
11. 6ठा 'भारतीय महिला जैविक उत्सव'
12. सिनेरियस गिद्ध

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

1. गगनयान के लिये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित
2. नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन
3. सुपर ब्लड वुल्फ मून (Super Blood Wolf Moon)
4. शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड'
5. भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री
6. उन्नति (UNNATI) कार्यक्रम
7. विज्ञान संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की पहल
8. सेना प्रौद्योगिकी सेमिनार (आरटेक-2019) (Army Tech Seminar -ARTECH 2019)
9. संपन्न (SAMPANN)
10. सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर
11. नासा ने की नए ग्रह की खोज
12. भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का 106वाँ अधिवेशन (106th Session of Indian Science Congress)
13. चीन का लूनर रोवर युतु-2
14. 'मदर ऑफ ऑल बॉम्स'

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

1. रोशनी एप (Roshni App)
2. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)
3. स्वच्छ शक्ति -2019 (Swachh Shakti-2019)
4. WebWonderWomen
5. लद्दाख की दर्द आर्यन जनजाति (Ladakh's Dard Aryan Tribes)

स्वास्थ्य (Health)

1. विश्व कुष्ठ दिवस
2. स्वाइन फ्लू (Swine Flu)
3. ई-औषधि पोर्टल (e-AUSHADHI portal)
4. ट्रांस फैटी एसिड पर जागरूकता अभियान
5. पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)
6. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान (National Deworming Day)
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority)

संस्कृति (Culture)

1. संगराई नृत्य (Sangrai Dance)
2. भारत पर्व
3. पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (Pakke Paga Hornbill Festival)
4. रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro)
5. जल्लीकट्टू (Jallikattu)
6. 'सांझी-मुझ में कलाकार' (SANJHI -MUJH MEIN KALAKAR)

7. अगस्त्यार्कूदम चोटी
8. ताज व्यू गार्डन (Taj View Garden)
9. सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम (Cultural Heritage Youth Leadership Programme-CHYLP)
10. बौद्ध सर्किट के अंतर्गत पाँच नई परियोजनाओं को मंज़ूरी
11. महामस्तकाभिषेक महोत्सव
12. गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा का अनावरण
13. स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत चार नई परियोजनाएँ
14. केरल में आध्यात्मिक सर्किट (Spiritual Circuit in Kerala)
15. कंबाला त्योहार/उत्सव (Kambala Festival)
16. विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day)
17. आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भित्तिचित्र स्थल

विविध (Miscellaneous)

1. साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018
2. 'ट्रेन 18' अब 'वंदे भारत एक्सप्रेस'
3. हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, 2018- नारी शक्ति
4. राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day)
5. सुभाष चंद्र बोस
6. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 (World University Ranking 2019)
7. गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize)
8. मोबाइल एप 'आरडीपी इंडिया 2019'
9. फिलिप कोटलर प्रेसीडेंशिअल अवार्ड
10. राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)
11. सावित्रीबाई फुले
12. 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स (70 points grading index)
13. सी विजिल 2019 (Sea Vigil 2019)

राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance)

9वाँ मतदाता दिवस

- 9वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day-NVD) 25 जनवरी 2019 को देशभर के 10 लाख मतदान केंद्रों पर मनाया जाएगा।
- आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस संस्करण की थीम 'नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड' चुनी गई है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे।
- एक त्रैमासिक पत्रिका, 'माई वोट मैटर्स' इस अवसर पर लॉन्च की जाएगी और इसकी पहली प्रति चुनाव आयोग द्वारा माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी।
- इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका जैसे चुनाव प्रबंधन निकायों (EMV) के प्रमुख/मुख्य चुनाव आयुक्त/आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी तथा मलेशियन कॉमनवेल्थ स्टडीज़ सेंटर, यूके; इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज़, यूके और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलैक्टोरल एसिस्टेंस (IDEA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख/वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

शुरुआत

- भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। 'भारत सरकार' ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस '25 जनवरी' को ही वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

उद्देश्य

- 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इसके लिये इस अवसर को सार्वभौम वयस्क मतदान को पूर्ण वास्तविकता बनाना और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- यह दिवस मतदाताओं के बीच मतदान प्रक्रिया में कारगर भागीदारी के बारे में जानकारी फैलाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष एक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' प्रस्तुत किया जाता है जिसे 'बजट' (Budget) कहते हैं।

- संसद में बजट पेश किये जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है तत्पश्चात् लोकसभा विभागानुसार 'अनुदान की मांगों' पर चर्चा करती है और उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन 'अनुदान की मांगों' (Demands For Grants) पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिये आवंटित राशि में कटौती की जाए तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है, इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या Cut Motion कहते हैं।

कटौती प्रस्ताव लाने के कारण

1. **सरकार की नीति को अस्वीकार करने के इरादे से :** इसमें संसद सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग की अनुदान मांगों में कटौती कर उसे केवल 1 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता हैं। ऐसा करने का स्पष्ट कारण यह है कि सदस्यों द्वारा सरकार

की उक्त नीति को अस्वीकार किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है तो सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति पैदा हो सकती है।

2. **इकॉनमी कट:** इसके अंतर्गत सदस्य किसी क्षेत्र की अनुदान मांगों में से एक निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव करते हैं लेकिन यह प्रस्ताव पेश करते समय सदस्यों को यह बताना होता है कि अनुदान की मांगों में आवंटित की गई राशि से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
3. **टोकन कट :** इसके अंतर्गत सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव करते हैं। सरकार से कोई विशेष शिकायत होने पर भी सदस्य ऐसा करते हैं।

लेकिन कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये स्वीकृति दी जाएगी अथवा नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।

कटौती प्रस्ताव का जवाब:
इस प्रस्ताव का जवाब उसी मंत्रालय के मंत्री द्वारा दिया जाता है जिसकी अनुदान की मांगों पर संसद में चर्चा की गई हो।

महत्त्व

- संसद सदस्य कटौती प्रस्ताव के ज़रिये बजट के संबंध में सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का काम करते हैं।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कटौती प्रस्ताव संसद सदस्यों के लिये एक प्रकार के वीटो पॉवर के समान है।

वोटर हेल्पलाईन एप, 'पीडब्ल्यूडी एप' और VVIP कार्यक्रम

- हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 के संचालन में 'सूचना और संचार तकनीक के उपयोग' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिये नागरिकों को उनके नाम, नए पंजीयन, ब्यौरे में बदलाव और मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिये मतदाता पुनरीक्षण और सूचना कार्यक्रम (Voter Verification and Information Programme -VVIP) लॉन्च किया।
- इस अवसर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को cVIGIL एप के प्रयोग की जानकारी दी गई।
- इस एप के माध्यम से आदर्श चुनाव संहिता के साक्ष्य आधारित सबूत, खर्च सीमा के उल्लंघन पर लाइव फोटो या वीडियो के ज़रिये कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। उल्लंघन कहाँ हुआ है, इसकी जानकारी GPS के ज़रिये स्वत: सम्बंधित अधिकारियों को मिल जाती है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा 'वोटर हेल्पलाईन' एप (Voter Helpline App) भी लॉन्च किया गया। इस एप की सहायता से नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने, ऑनलाइन फार्म जमा करने, आवेदन की स्थिति जानने और शिकायत दर्ज करने जैसी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते है।
- इस दौरान दिव्यांगजनों के लिये विशेष सुविधा प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग ने 'पीडब्ल्यूडी एप' (PwD App) भी लॉन्च किया। इस एप की सहायता से दिव्यांगजन अपनी पहचान का पंजीयन कर सकते हैं, पते और अन्य ब्यौरे में बदलाव कर सकते हैं। चुनाव के दौरान दिव्यांगजन व्हिलचेयर की मांग भी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)

- रंगराजन आयोग ने 2001 में भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National statistics commission-NSC) की स्थापना की सिफारिश की थी। जिसके तहत 2005 में एक प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने NSC की स्थापना कर दी थी।
- NSC सांख्यिकीय मामलों पर सर्वोच्च सलाहकारी निकाय है क्योंकि इसका गठन सांख्यिकीय मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करने के लिये ही किया गया था।

- NSC में एक अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सदस्य निर्दिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अनुभवी होता है।

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 (National Youth Parliament Festival 2019)

हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 की शुरुआत की।

- इस महोत्सव की शुरुआत राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) के अवसर पर की गई तथा इसकी प्रक्रिया 24 फरवरी, 2019 तक जारी रहेगी।
- इस महोत्सव का आयोजन तीन स्तरों पर किया जाएगा-

1. ज़िला स्तर पर- ज़िला युवा संसद (District Youth Parliament-DYP)
2. राज्य स्तर पर- राज्य युवा संसद (State Youth Parliament-SYP)
3. राष्ट्रीय स्तर पर- राष्ट्रीय युवा संसद (National Youth Parliament-NYP)

- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 को **"नए भारत की आवाज़ बनो"** तथा **"उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो"** (Be The Voice of New India and Find solutions and contribute to policy) की थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangthan) इसके संचालन और प्रबंधन में विभिन्न स्तरों पर शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय युवा संसद के तीन सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को प्रधानमंत्री द्वारा क्रमश: 2 लाख, 1.50 लाख और 1 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

विजय माल्या को देश का पहला भगौड़ा आर्थिक अपराधी (fugitive economic offender) घोषित किया गया है।

कौन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी?

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके खिलाफ किसी अपराध (अनुसूची में दर्ज) के संबंध में गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति ने-

1. मुक़दमे से बचने के लिये देश छोड़ दिया है या
2. मुकदमे का सामना करने से बचने के लिये देश लौटने से इनकार कर दिया हो।

अनुसूची में दर्ज अपराधों में से कुछ प्रमुख अपराध इस प्रकार हैं-

- नकली सरकारी स्टाम्प या करेंसी बनाना।
- पर्याप्त धन न होने के कारण चेक का भुनाया न जाना।
- मनी लॉन्ड्रिंग।
- क्रेडिटर्स के साथ लेन-देन में धोखाधड़ी करना।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations)

अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) का आह्वान

हाल ही में मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (Central Marine Fisheries Research Institute-CMFRI) में 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- **इस कार्यशाला में AARDO के 12 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।**
- **अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान संयुक्त एशियाई प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिये अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान किया गया।**
- **ओमान, लेबनान, ताइवान, मोरक्को, सीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ज़ाम्बिया, मलावी, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने बेहतर मत्स्य प्रबंधन पहल शुरू करने के लिये आपसी सहयोग की मांग की।**

अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO)

- **इसका गठन 1962 में किया गया जिसमें अफ्रीका और एशिया के देशों की सरकारें शामिल हैं।**
- **AARDO एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका देशों के बीच कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग कर उस पर कार्य करना है।**

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI)

- **इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी, 1947 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।**
- **1967 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) में शामिल कर दिया गया। अब यह संस्थान दुनिया के उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है।**

भारत-रूस संबंध

हाल ही में भारत में रूसी राजदूत निकोले आर. कुदाशेव ने भारत-रूस संबंध का हवाला देते हुए कहा है कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का सौदा दोनों देशों के बीच साझेदारी की विशेष प्रकृति का प्रमाण है।

क्या है S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली?

- **रूस के अल्माज़ केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है।**
- **यह मिसाइल प्रणाली रूस में 2007 से सेवा में है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है।**
- **S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है।**
- **S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है, जो इसके 400 किमी. की रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं पाँचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकती है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है।**
- **इस प्रणाली में एक साथ तीन मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं, जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं।**
- **इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ज़मीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।**
- **इससे पहले चीन ने 2014 में छह S-400 के लिये 3 बिलियन डॉलर का रक्षा सौदा रूस के साथ किया था और चीन को अब इनकी आपूर्ति भी होने लगी है।**
- **दिसंबर 2017 में तुर्की ने ऐसी दो प्रणालियों के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।**

भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास-2019

India-Africa Field Training Exercise (IAFTX)- 2019

भारतीय अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (IAFTX)-2019 की तैयारियों से संबंधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिये पुणे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- इस अभ्यास से संबंधित प्रारंभिक योजना दिसंबर 2018 में आयोजित सम्मेलन में ही तैयार कर ली गई थी।
- इस सम्मेलन में मिस्र (Egypt), घाना (Ghana), नाइजीरिया (Nigeria), सेनेगल (Senegal), सूडान (Sudan), दक्षिण अफ्रीका (South Africa), तंज़ानिया (Tanzania), नामीबिया (Namibia), मोज़ाम्बिक (Mozambique), युगांडा (Uganda), नाइजर (Niger) और जाम्बिया (Zambia) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- IAFTX-2019 का आयोजन 18 से 27 मार्च, 2019 तक पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन (Aundh Military Station) और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (College of Military Engineering) में किया जाएगा।
- यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों के बीच किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों को बढ़ाने और संयुक्त शांति अभियानों को गति देना है।
- IAFTX-2019 अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य राष्ट्रों के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इससे इन देशों के साथ पहले से ही मज़बूत रणनीतिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas-PBD)

15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

- इस बार प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas-PBD) सम्मेलन की **थीम 'नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' (Role of Indian Diaspora in building New India)** है।
- 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 7 से 9 जनवरी, 2017 को बंगलूरू, कर्नाटक में किया गया था जिसकी थीम **'प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को पुनर्भाषित करना' (Redefining Engagement with the Indian Diaspora)** थी।
- सम्मेलन के दौरान भारत के साथ-साथ विदेशों के भी विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों का चयन किया जाता है तथा उनके योगदान को मान्यता देने के लिये प्रतिष्ठित **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (Pravasi Bharatiya Samman Award)** से सम्मानित किया जाता है।
- PBDA प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

पृष्ठभूमि

- प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था।
- पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिये 9 जनवरी का दिन इसलिये चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।
- अब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर दो साल में एक बार किया जाता है।
- यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ो से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध कराता है।

आसियान-भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक (ASEAN-India Tourism Ministers meeting)

हाल ही में वियतनाम के हा लोंग (Ha Long City) शहर में आसियान (ASEAN) तथा भारत के पर्यटन मंत्रियों के बीच सातवीं बैठक का आयोजन किया गया।

- भारत के पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फोंस (K. J. Alphons) ने वियतनाम के संस्कृति, खेल तथा पर्यटन मंत्री के साथ पर्यटन मंत्रियों की इस बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- इस बैठक में ब्रुनेई दारेसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्याँमार, फिलिपिंस, सिंगापुर तथा थाईलैंड के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए।
- इस बैठक के दौरान पर्यटन मंत्रियों ने 2018 में आसियान तथा भारत के पर्यटन प्रदर्शन पर विचार किया गया। उल्लेखनीय है कि 2018 में आसियान तथा भारत में 139.5 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।

ASEAN

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन- आसियान (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में की गई थी।
- थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर इसके संस्थापक सदस्य थे।
- वर्तमान में ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

उद्देश्य

- आसियान के सदस्य देश आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने के लिये साझा प्रयास करते हैं।
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- चूँकि आसियान इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और व्यावसायिक चौराहा प्रस्तुत करता है, इसलिये इसके पास इससे आगे बढ़कर दुनिया के व्यापक हितों को आगे बढ़ाने और संतुलित करने की अनोखी क्षमता है।

भारत सबसे भरोसेमंद देशों में से एक (India Among The Most Trusted Nations)

सरकार, व्यापार, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और मीडिया की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर सबसे भरोसेमंद देशों में से एक है।

- एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर (Edelman Trust Barometer) रिपोर्ट 2019, जो दावोस में आयोजित हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) की बैठक से ठीक पहले जारी की गई है, के अनुसार वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक (Global Trust Index) तीन अंकों की मामूली वृद्धि के साथ 52 अंकों तक पहुँच गया है।
- **जागरूक जनता सूचकांक** में 79 और सामान्य आबादी के भरोसा सूचकांक में 88 अंकों के साथ चीन इस सूचकांक में सबसे ऊपर है।
- भारत जागरूक जनता की श्रेणी में दूसरे स्थान पर और सामान्य आबादी श्रेणी में तीसरे स्थान पर है।
- ये निष्कर्ष 16 अक्तूबर से 16 नवंबर, 2018 तक 27 बाज़ारों में कराए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसमें 33,000 से अधिक लोगों के जवाब को शामिल किया गया है।
- ब्रांड संबंधी विश्वसनीयता के मामले में उन कंपनियों का नाम आता है जिनके मुख्यालय स्विटज़रलैंड, जर्मनी और कनाडा में हैं। इसके बाद जापान का स्थान आता है। वहीं भारत, मेक्सिको और ब्राज़ील में स्थित कंपनियाँ भरोसे के मामले में निचले स्थानों पर हैं। इसके बाद चीन और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है।

- **एडेलमैन (Edelman)** एक वैश्विक संचार विपणन फर्म है जो दुनिया के प्रमुख व्यवसायों और संगठनों के ब्रांड और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिये उनके साथ भागीदार के रूप में कार्य करती है।

भारत सरकार और JICA के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर (The Government of India and JICA sign Loan Agreements)

जापान के सरकारी विकास सहायता ऋण कार्यक्रम (Japanese Official Development Assistance Loan Program) के अंतर्गत भारत सरकार और JICA (Japan International Cooperation Agency) के बीच ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

दोनों देशों के बीच यह समझौता निम्नलिखित कार्यों के लिये किया गया है-

चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड (Chennai Peripheral Ring Road)-चरण 1 निर्माण परियोजना हेतु 40.074 बिलियन जापानी येन की सहायता।

- इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई महानगर क्षेत्र में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करना है, जिसे चेन्नई बाहरी रिंग रोड (सेक्टर-1) बनाकर तथा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट प्रणाली स्थापित करके पूरा किया जा सकता है।
- इससे यातायात भीड़-भाड़ में कमी होगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्य के लिये 15000 बिलियन जापानी येन की सहायता

- इसका उद्देश्य भारत में SDGs के प्रोत्साहन में योगदान करना, विशेषकर भारत सरकार के प्रयासों को समर्थन देकर सामाजिक विकास करना और नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन व्यवस्था को मज़बूत बनाना है।

पृष्ठभूमि

भारत और जापान के बीच 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग (Bilateral Development Cooperation) का लंबा इतिहास रहा है। भारत-जापान आर्थिक सहयोग में तेजी से प्रगति हुई है। यह भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मज़बूत बनाता है।

भारत ने जर्मनी और स्वीडन के साथ रक्षा समझौतों पर किये हस्ताक्षर

भारत ने जर्मनी और स्वीडन दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग और सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत और स्वीडन के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिससे दोनों देश एक- दूसरे के साथ गोपनीय जानकारी को साझा करने में सक्षम होंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत और स्वीडन ने वर्ष 2009 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
- इससे पहले जर्मनी में रक्षा मंत्री ने रक्षा और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु उपायों को लागू करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिससे दोनों देशों की सेनाओं के साथ रक्षा उद्योग और अनुसंधान तथा विकास संबंधों को और मज़बूत बनाया जा सकेगा।
- जर्मनी और स्वीडन दोनों ही भारत को रक्षा उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता हैं और उनकी कंपनियाँ इस समय पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिये कई निविदाओं की प्राप्ति के लिये प्रयासरत हैं।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalised System of Preferences-GSP)

यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (US Trade Representative-USTR) भारत के लिये वरीयता व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अमेरिका सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के तहत कुछ निश्चित निर्यात सीमा पर भारत से कोई शुल्क नहीं लेता है।

- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली विकसित देशों (वरीयता देने वाले या दाता देश) द्वारा विकासशील देशों (वरीयता प्राप्तकर्त्ता या लाभार्थी देश) के लिये विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है।
- गौरतलब है कि इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।
- इसके ज़रिये विकसित देश विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- नामित लाभार्थी विकासशील देशों के लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादों के लिये वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। भारत भी एक लाभार्थी विकासशील देश है।
- ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कज़ाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका GSP वरीयताएँ देते हैं।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalised System of Preferences-GSP)

यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (US Trade Representative-USTR) भारत के लिये वरीयता व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अमेरिका सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के तहत कुछ निश्चित निर्यात सीमा पर भारत से कोई शुल्क नहीं लेता है।

- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली विकसित देशों (वरीयता देने वाले या दाता देश) द्वारा विकासशील देशों (वरीयता प्राप्तकर्त्ता या लाभार्थी देश) के लिये विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है।
- गौरतलब है कि इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।
- इसके ज़रिये विकसित देश विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- नामित लाभार्थी विकासशील देशों के लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादों के लिये वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। भारत भी एक लाभार्थी विकासशील देश है।
- ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कज़ाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका GSP वरीयताएँ देते हैं।

राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal)

हाल ही में जस्टिस एके सीकरी ने सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) में नामित किया जाना था।

- राष्ट्रमंडल सचिवालय राष्ट्रमंडल की मुख्य अंतर सरकारी एजेंसी और केंद्रीय संस्थान है।
- यह सचिवालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यह अपने 53 सदस्य देशों के बीच विवाद की स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) में अध्यक्ष सहित कुल आठ सदस्य होते हैं।
- राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।

नो इंडिया प्रोग्राम (Know India Programm)

हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा KIP (Know India Programm) का 25 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- KIP भारतीय राज्यों के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है।
- भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित यह प्रवासी युवाओं के लिये कार्यक्रम है।
- इसमें 40 प्रतिभागी हैं, जिनमें 26 महिलाएँ हैं। ये प्रतिभागी मुख्यतः 8 देशों से आए हैं।
- यह योजना 2004 में शुरू की गई थी और तब से अब तक विदेश मंत्रालय ने KIP के 49 संस्करणों का आयोजन किया है, जिनमें 1600 से अधिक प्रवासी भारतीय युवाओं द्वारा सहभागिता की गई।

उद्देश्य

- भारत से जुड़ने के लिये 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय डायस्पोरा के छात्रों और युवा पेशेवरों को शामिल करना।
- युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें भारतीय कला, विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं एवं भारत द्वारा की गई प्रगति के बारे में जागरूक करना।

अर्थव्यवस्था (Economy)

रत्न और आभूषण के लिये घरेलू परिषद

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रत्न और आभूषण के लिये एक घरेलू परिषद (Domestic Council for Gems & Jewellery) के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रत्न और आभूषण उद्योग के घरेलू व्यापारिक हितधारकों को एक छत के नीचे लाना है ताकि वे इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण विकसित कर सकें।
- यह परिषद पहले से मौजूद बड़े घरेलू बाज़ार में नए अवसरों को भुनाने में मदद करेगी।
- सरकार का मूल उद्देश्य इस असंगठित क्षेत्र को संगठित तथा संरचित बनाना है ताकि अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजित किये जा सकें।
- 2018 तक रत्न और आभूषण का खुदरा घरेलू कारोबार लगभग 4 लाख करोड़ रूपए का रहा है। वर्तमान में यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुज़र रहा है।
- रत्न और आभूषण के निर्यात में आभूषण की हिस्सेदारी कम है और उक्त परिषद इस हिस्सेदारी को बढ़ाने पर ध्यान देगी।

अटल सेतु (Atal Setu)

- हाल ही में गोवा में मांडोवी (Mandovi) नदी पर अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है।
- यह राज्य की राजधानी पणजी को उत्तरी गोवा से जोड़ने वाला 5.1 किलोमीटर लंबा केबल स्टे (स्टील की केबल के सहारे लटका हुआ) ब्रिज है।
- मांडोवी, जिसे महादयी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के उत्तरी भाग के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। यह नदी कर्नाटक के बेलगाँव ज़िले में उत्पन्न होती है और महाराष्ट्र तथा गोवा से गुजरती हुई अरब सागर में जा मिलती है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश

विश्व इस्पात संघ (World Steel Association-worldsteel) के अनुसार, भारत जापान को प्रतिस्थापित कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, जबकि चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में 51 प्रतिशत से अधिक भागीदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है।

शीर्ष दस में शामिल देश इस प्रकार हैं-

रैंकिंग	देश
1	चीन
2	भारत
3	जापान
4	संयुक्त राज्य अमेरिका

5	**दक्षिण कोरिया**
6	**रूस**
7	**ज़र्मनी**
8	**तुर्की**
9	**ब्राज़ील**
10	**ईरान**

विश्व इस्पात संघ (World Steel Association-worldsteel)

- विश्व इस्पात संघ (worldsteel) दुनिया के प्रमुख उद्योग संघों में से एक है।
- इसकी स्थापना 10 जुलाई, 1967 को **अंतर्राष्ट्रीय लौह एवं इस्पात संस्थान (International Iron and Steel Institute)** के रूप में की गई थी। 6 अक्तूबर, 2008 को इसका नाम बदलकर **विश्व इस्पात संघ/वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (World Steel Association)** कर दिया गया।
- इसका **मुख्यालय ब्रुसेल्स** (बेल्जियम) में है।
- worldsteel 160 से अधिक इस्पात उत्पादकों (दुनिया की 10 सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से 9 सहित), राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघों और इस्पात अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके सदस्य देश दुनिया के कुल इस्पात उत्पादन के लगभग 85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक - 2019 (Global Talent Competitive Index 2019)

- हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 2019 में भारत को 80वाँ स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में जारी इस सूचकांक में भारत को 81वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- इस सूचकांक के अंतर्गत वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा में देशों की क्षमता की माप की जाती है।
- इसे इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल द्वारा टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) और एडिको समूह (Adecco Group) के सहयोग से जारी किया गया है।
- इस बार सूचकांक की थीम **'उद्यमी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा' (Entrepreneurial Talent and Global Competitiveness)** है।
- इस बार सूचकांक में 125 देशों को शामिल किया गया है।
- सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमशः स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, नॉर्वे तथा डेनमार्क हैं।
- यह सूचकांक कुछ मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है जैसे कि नियुक्ति में सहजता, लैंगिक आधार पर आय में असमानता एवं व्यवसाय का प्रसार।
- इस बार भारत की सबसे प्रमुख चुनौती प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने की अपनी क्षमता में सुधार करना है।
- भारत को बढ़ती लैंगिक असमानता तथा अल्पसंख्यकों और अप्रवासी के प्रति असहिष्णुता के संबंध में आंतरिक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है।

केरियन गंडियाल पुल (Kerrian Gandyal bridge)

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जम्मू के कठुआ ज़िले में निर्मित केरियन गंडियाल पुल को राष्ट्र को समर्पित किया।

- इस पुल का निर्माण कठुआ ज़िले में रावी नदी पर किया गया है और इसके निर्माण में तीन साल का समय लगा है।
- रावी नदी पर 1.2 किमी लंबे इस पुल का निर्माण 158.84 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इससे अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क में सुधार होगा।
- इस परियोजना से जम्मू के कठुआ और पंजाब के पठानकोट में रहने वाले लगभग 2,20,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
- इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर से घटकर 8.6 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन (Vibrant Gujarat Summit)

18 जनवरी, 2019 को गांधीनगर (गुजरात) स्थित महात्मा गांधी प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र (Mahatma Mandir Exhibition cum Convention Centre) में वाइब्रेंट गुजरात का 9वाँ संस्करण शुरू हुआ।

थीम- शेपिंग ए न्यू इंडिया (Shaping a New India)

- इस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में उज़्बेकिस्तान, रवांडा, डेनमार्क, चेक गणराज्य और माल्टा के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित थे।
- उद्योगजगत के प्रतिनिधियों समेत 30 हज़ार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं।
- इस शिखर सम्मलेन के भागीदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्राँस, जापान, मोरक्को, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान शामिल हैं.
- यह शिखर सम्मेलन वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने और प्रभावकारी साझेदारियाँ करने से जुड़े एजेंडे पर विचार मंथन करने के लिये एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।

पृष्ठभूमि

- 'वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन' की परिकल्पना वर्ष 2003 में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
- इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुजरात को फिर से एक पसंदीदा निवेश गंतव्य या राज्य के रूप में स्थापित करना था।

कुसुम योजना (KUSUM Scheme)

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि सरकार किसानों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये **'कुसुम' (KUSUM)** नामक योजना तैयार कर रही है।

- इस योजना का पूरा नाम 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) है।
- प्रस्तावित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का प्रावधान किया गया है-
- ग्रामीण इलाकों में 500KW से 2 MW तक की क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- ऐसे किसानों, जो किसी भी ग्रिड से नहीं जुड़े हैं, की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एकल आधार वाले (stand alone) ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना।
- किसानों को ग्रिड से की जाने वाली आपूर्ति से मुक्त करने के लिये विद्यमान ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarization) तथा उत्पादित अधिशेष सौर ऊर्जा की बिक्री वितरण कंपनियों (Distribution Companies-DISCOM) को करना और अतिरिक्त आय प्राप्त करना।
- यह योजना सरकार के विचाराधीन है इसलिये, विस्तृत प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है।

सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt)

केंद्र सरकार ने सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र अथवा स्टैटस पेपर (Status Paper) का आठवाँ संस्करण जारी किया है।

- इस स्थिति-पत्र में भारत सरकार की समग्र ऋण संबंधी स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- केंद्र सरकार वर्ष 2010-11 से ही सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति-पत्र (Annual Status Paper on Government Debt) जारी करती रही है।
- यह स्थिति-पत्र वर्ष के दौरान ऋण संबंधी परिचालनों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य ऋण प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित सार्वजनिक ऋण के पोर्टफोलियो की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करके पारदर्शिता को बढ़ाता है।
- इस स्टैटस पेपर में वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण संबंधी परिचालनों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिये मुख्यत: बाज़ार से जुड़ी उधारियाँ लेती है। ऋण संबंधी स्थायित्व के पारंपरिक संकेतकों यथा ऋण/GDP अनुपात, कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण/विदेशी कर्ज/FRB की हिस्सेदारी इत्यादि से यह पता चलता है कि सरकार का ऋण पोर्टफोलियो विशेषकर ऋण स्थायित्व पैमानों की दृष्टि से संतोषजनक है और इसमें निरंतर बेहतरी हो रही है।
- स्टैटस पेपर में वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक के लिये केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति (Debt Management Strategy) का भी उल्लेख किया गया है, जो सरकार की उधारी योजना का मार्गदर्शन करेगी।

'राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस' (National Productivity Day)

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council-NPC) ने **12 फरवरी**, 2019 को अपना 61वाँ स्थापना दिवस मनाया। NPC अपने स्थापना दिवस को **'उत्पादकता दिवस'** के रूप में मनाता है।

परिषद के बारे में

- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा **वर्ष 1958 में स्थापित** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एक स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय और गैर-लाभान्वित संगठन है।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिये शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना है।
- यह परिषद टोक्यो स्थित अंतःशासकीय निकाय, **एशियाई उत्पादकता संगठन (Asian Productivity Organisation-APO)** का एक घटक है। उल्लेखनीय है कि भारत APO के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह (National Productivity Week)

- NPC 12-18 फरवरी, 2019 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन भी कर रहा है।
- इस वर्ष के राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम है **'उत्पादकता और निरंतरता के लिये सर्कुलर अर्थव्यवस्था' ('Circular Economy for Productivity and Continuity')।**

- सर्कुलर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था **'बनाओ, उपयोग करो, वापस पाओ' (Make-Use-Return)** से जुड़े सर्कुलर बिजनेस मॉडल के लिये अनूठे अवसर को परिलक्षित करती है।

एक्वा मेगा फूड पार्क (Aqua Mega Food Park)

12 फरवरी, 2018 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले में भीमावरम मंडल के टुंडुरू गाँव में **गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क (Godavari Aqua Mega Food Park)** का उद्घाटन किया गया।

- इस पार्क का विकास मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड (M/s Godavari Mega Aqua Food Park Pvt. Ltd.) द्वारा किया गया है।
- यह आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिये विशेष रूप से स्थापित पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है।
- गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क 122.60 करोड़ रुपए की लागत से 57.81 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।
- आंध्र प्रदेश के अन्य मेगा फ़ूड पार्क चित्तूर ज़िले में तथा कृष्णा ज़िले में हैं। इनमें से चित्तूर स्थित मेगा फ़ूड पार्क की शुरुआत 9 जुलाई, 2012 को ही हो चुकी थी जबकि कृष्णा ज़िले में मेगा फ़ूड पार्क स्थापित करने का कार्य अभी प्रगति पर है।

पृष्ठभूमि

- मेगा फूड पार्क योजना का कार्यान्वयन **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)** द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाज़ार से जोड़ने हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्द्धन, न्यूनतम बर्बादी, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके।
- मेगा फूड पार्क स्कीम **'क्लस्टर'** दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें पार्कों में सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिये सुपरिभाषित कृषि/बागवानी ज़ोन में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है।
- मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों, शीत श्रृंखला और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु 30-35 पूर्ण विकसित भूखंडों समेत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना शामिल होती है।

देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

हाल ही में केरल में देश के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का उद्घाटन किया गया जिसमें देश की तकनीकी, चिकित्सा, संचार प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में 1.8 लाख वर्ग फुट की सुविधा वाले आवास ऊष्मायन (Housing Incubation) की स्थापना की गई।
- केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) के तहत इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स (Integrated Startup Complex) में 'मेकर विलेज' (Maker Village) की अत्याधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं जो हार्डवेयर स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं जैसे कि बायोनेस्ट (BioNest) जो चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, ब्रिंक (BRINC) हार्डवेयर स्टार्टअप के लिये देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहल है, BRIC जो कैंसर के निदान और देखभाल के लिये समाधान विकसित कर रहा है एवं उद्योग की बड़ी कंपनियों जैसे-UNITY द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र आदि।
- केरल सरकार राज्य में स्टार्टअप के लिये इस वर्ष 2.3 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्रफल (पिछले साल के 1.3 करोड़ वर्ग फुट से अधिक) पर काम कर रही है। प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र (Technology Innovation Zone -TIZ) में नए परिसर का उद्घाटन इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- अधिकारियों ने बताया कि TIZ देश का सबसे बड़ा 'वर्क-लाइव-प्ले स्पेस' बनने के लिये तैयार है, जो विशेष रूप से स्टार्टअप के लिये समर्पित है। मेकर विलेज, जिसे आईआईआईटीएम (IIITM) के द्वारा KSUM के सहयोग से स्थापित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

'लाइट हाउस परियोजना चुनौती' (Light House Project Challenge)

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs-MoHUA) ने GHTC-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूरे देश में 6 स्थलों का चयन करने के लिये राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये एक चुनौती की शुरुआत की है।

- इस चुनौती के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लाइट हाउस परियोजनाएँ प्रदान की जाएंगी। इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के निर्माण के लिये केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (Technology Innovation Grant-TIG) का भी प्रावधान किया गया है।

GHTC-इंडिया

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय पहले ही वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-इंडिया (Global Housing Technology Challenge-India) की शुरूआत कर चुका है। इस चुनौती के तीन घटक हैं-

1. ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना।
2. दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना।
3. उष्मायन और त्वरित सहायता के लिये किफायती, स्थायी आवास की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
4. अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

मोबाइल-एप ई-कोकून

हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन ई-कोकून लॉन्च किया है। गौरतलब है कि यह एप्लीकेशन रेशम कीट बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिये उपयोग में लाया जाएगा।

- मोबाइल ऐप ई-कोकून रेशम कीट बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन में मदद करेगा क्योंकि रियल टाइम रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रणाली और उत्पाद प्रमाणन हेतु इसका उपयोग केंद्रीय बीज अधिनियम के तहत नामित बीज विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- भारत एकमात्र ज्ञात ऐसा देश है, जो सभी पाँच ज्ञात वाणिज्यिक रेशम- शहतूत, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, एरी और मुगा का उत्पादन करता है।
- गैर-शहतूत रेशम या वन्या सिल्क (तसर, एरी और मुगा) का उत्पादन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है।
- नॉर्थ-ईस्ट एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेशम की चार किस्मों -शहतूत, ओक तसर, मुगा और एरी का उत्पादन होता है।
- चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।

पेट्रोटेक- 2019

प्रधानमंत्री द्वारा 11 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में पेट्रोटेक (PETROTECH)-2019 का उद्घाटन किया जाना है।

- भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्त्वाधान में 13वाँ अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी (PETROTECH-2019) का आयोजन किया जा रहा है।
- पेट्रोटेक - 2019 को भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन माना जाता है।
- यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 10-12 फरवरी, 2019 तक आयोजित किया जाएगा।
- PETROTECH-2019 प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और अक्षय ऊर्जा थीम पर विशेष क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाज़ार और निवेशकों के अनुकूल विकास को दर्शाया जाएगा।

देश की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग

हाल ही में 10.7 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जिसमें 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है को जोड़कर विज़िंजम इंटरनेशनल मल्टीपर्पज़ डीपवाटर सीपोर्ट (Vizhinjam International Multipurpose Deepwater Seaport) को रेलवे नेटवर्क से जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया।

- **मई 2022 तक यह रेलवे लिंक स्थापित किये जाने की योजना है।**
- **कन्याकुमारी-तिरुवनंतपुरम रेलवे लाइन पर बलरामपुरम स्टेशन के पास कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Konkan Railway Corporation Ltd-KRCL) द्वारा प्रस्तावित यह सुरंग पूरी हो जाने पर देश की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी।**
- **केंद्रीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd-RVNL) द्वारा इस परियोजना से हाथ खींचे जाने के बाद KRCL को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई जिसे सुरंग निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है।**

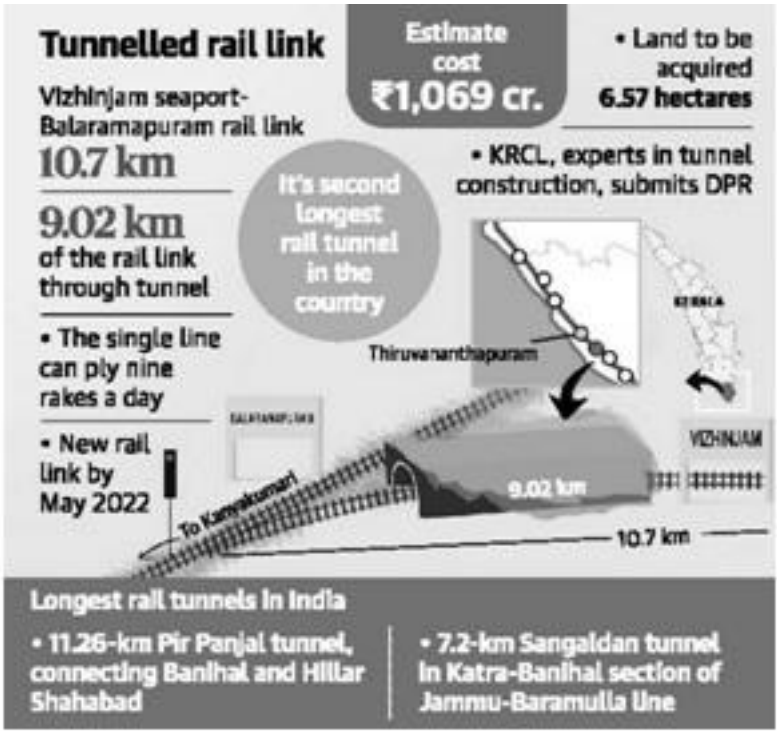

- **बलरामपुरम रेलवे स्टेशन के विकास को सीपोर्ट के रेल लिंक के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।**
- **विज़िंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड इस विशेष प्रयोजन हेतु एक कंपनी है जो सीपोर्ट परियोजना के निष्पादन की देखरेख कर रही है।**
- **KRCL के अनुसार, बलरामपुरम से विज़िंजम तक प्रस्तावित रेलवे लाइन, सिंगल लाइन होगी और आने वाले 20 सालों तक सुगमता पूर्वक संचालित होगी।**

वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Womaniya on Government e Marketplace)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने **'वुमनिया ऑन GeM'** पहल की शुरुआत की है।

- GeM की इस पहल का उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों के ज़रिये महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को हस्तशिल्प एवं हथकरघा, सहायक सामग्री, जूट उत्पाद, घरों के साज-सजावट के सामानों की सीधे बिक्री करने में सहायता प्रदान करना है।
- GeM की इस पहल से महिला उद्यमियों को समेकित आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।
- वुमनिया वेबसाइट के होम पेज पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) हेतु महिला उद्यमियों की सेवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये अभियान के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- वुमनिया ऑन GeM महिला उद्यमियों के लिये आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा जिससे **संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 5 - 'लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करें'** के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

GeM

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e Marketplace) एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)** के तहत की गई है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का **संक्षिप्त रूप जेम (GeM)** है जहाँ सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिये जेम गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता अनुकूल पोर्टल है।

ओवरड्राफ्ट (Overdraft)

हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत **ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए** करने का फैसला किया है।

क्या होता है ओवरड्राफ्ट?

- जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में जमाराशि से अधिक धनराशि निकालता है और खाते में उसका बैलेंस शून्य से नीचे चला जाता है तो उसे 'ओवरड्राफ्ट' कहते हैं।
- ओवरड्राफ्ट **एक प्रकार की कर्ज़ सुविधा** है जो बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा होने पर उपलब्ध होती है।
- इसके ज़रिये खाताधारक अचानक आवश्यकता पड़ने पर बैंक से कुछ समय के लिये उधार ले सकता है। लेकिन वह एक निर्धारित सीमा जिसे 'ओवरड्राफ्ट लिमिट' कहते है, तक ही उधार ले सकता है।
- बैंक खाताधारक की साख और उसके खाते द्वारा किये गए हस्तांतरण के आधार पर **ओवरड्राफ्ट लिमिट** का निर्धारण करता है।
- **प्रधानमंत्री जन-धन योजना** के अंतर्गत यह सुविधा **परिवार में केवल एक सदस्य (विशेष रूप से महिला) के लिये** उपलब्ध होती है।
- 2,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट हेतु कोई शर्त नहीं रखी गई है और यह सुविधा 18-65 आयु वर्ग के लोगों के लिये उपलब्ध है।

ओवरड्राफ्ट पर भी देना पड़ता है ब्याज

- जिस प्रकार से बैंक अन्य ऋणों पर ब्याज वसूलता है उसी प्रकार ओवरड्राफ्ट पर भी ग्राहक को ब्याज की अदायगी करनी पड़ती है। हालाँकि, ब्याज की यह दर क्रेडिट कार्ड के ज़रिये मिलने वाले उधार की तुलना में कम भी हो सकती है।

लाभ

- खाते में धनराशि कम होने पर भी कोई आवश्यक काम नहीं रुकता है, जैसे- एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को चेक दिया और जब दूसरा व्यक्ति उस चेक को भुनाने के लिये बैंक गया, तब तक पहले व्यक्ति के खाते में मौज़ूद धनराशि चेक की राशि से कम हो गई तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस हो सकता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा होने पर बैंक उस चेक को क्लियर कर देगा और इस प्रकार भुगतान करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज (Country's Longest Single Lane Steel Cable Bridge)

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे लंबे (300 मीटर) सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया।

- ऊपरी सियांग (Upper Siang) ज़िले के यिंगकिओंग (Yingkiong) में सियांग नदी पर बने इस पुल का नाम ब्योरुंग ब्रिज (Byorung Bridge) रखा गया है।
- इस पुल का निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (Department for Development of North Eastern Region-DONER) मंत्रालय द्वारा प्रदत्त 48.43 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
- इस पुल के कारण यिंगकिओंग से तूतिंग (Tuting) के बीच की दूरी लगभग 40 किमी. कम हो जाएगी। पुल के निर्माण से पहले इनके बीच सड़क मार्ग से कुल दूरी 192 किमी. थी।
- इस पुल के निर्माण से रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के अलावा, नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले 20,000 लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (Electronic National Agriculture Market e-NAM)

हाल ही में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पहली बार अंतर-राज्यीय लेन-देन के स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म ई-नाम (e-NAM) का आयोजन किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल (Electronic Trading Portal) है, जो मौजूदा कृषि उपज बाज़ार समिति (Agricultural Produce Market Committee - APMC) मंडियों को कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिये नेटवर्क प्रदान करता है। इसे 2016 में शुरु किया गया था।
- e-NAM मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों के माध्यम से मंडियों में वस्तुओं के व्यापार करने की अनुमति देता है।
- लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (Small Farmers Agribusiness Consortium-SFAC) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो e-NAM को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- राज्यों को e-NAM व्यवस्था अपनाने के लिये निम्नलिखित परिवर्तन की आवश्यकता है-
    - इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करना।
    - एकल व्यापार लाइसेंस प्रदान करना जो राज्य की सभी मंडियों में मान्य हों।
    - लेन-देन शुल्क की एकल-खिड़की व्यवस्था लागू करना।
- e-NAM पोर्टल सभी कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) से संबंधित जानकारी और सेवाओं के लिये एक एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के साथ वस्तुओं के आयात और मूल्य, व्यापार ऑफर खरीदना और बेचना, व्यापार ऑफर पर प्रतिक्रिया देने का प्रावधान शामिल है।

फ्रिंज बेनिफिट (Fringe Benefit)

जब किसी कंपनी या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन या भत्ते के अलावा कुछ अन्य सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं तो इन अतिरिक्त सेवाओं को फ्रिंज बेनिफिट (Fringe Benefit) कहते हैं।

- फ्रिंज बेनिफिट के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, समूह बीमा, शैक्षिक सहायता, बच्चे की देखभाल और उससे संबंधित सहायता राशि, कैफेटेरिया की सुविधा और व्यक्तिगत उपयोग हेतु कंपनी द्वारा वाहन उपलब्ध कराने जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
- इसके माध्यम से कंपनियाँ अपने कुछ कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिये पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प देती हैं लेकिन ये शेयर ESO, स्टॉक एक्सचेंज में खरीद-बिक्री किये जाने वाले शेयरों से अलग होते हैं क्योंकि इन्हें शेयर बाज़ार में ख़रीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता है।
- कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प देने के पीछे तर्क यह है कि जब वे कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो स्वयं भी कंपनी के शेयरों की मज़बूती के लिये परिश्रम करेंगे।
- आमतौर पर फ्रिंज बेनिफिट कर-मुक्त होते हैं लेकिन कभी-कभी सरकार इनको कर के दायरे में ले आती है जैसे- सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2005 के ज़रिये फ्रिंज बेनिफिट्स पर आयकर लागू किया जाना जो अप्रैल 2006 से प्रभाव में आया था लेकिन भारी विरोध के बाद फाइनेंस एक्ट, 2009 के ज़रिये इसे वापिस ले लिया गया।

लाभ-

फ्रिंज बेनिफिट से न केवल कर्मचारियों को मदद मिलती है बल्कि कंपनियों को भी भर्ती के समय प्रतिभावान कर्मचारियों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। इसलिये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ भर्ती के समय फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफर करती हैं।

कड़कनाथ मुर्गा

हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को टीम इंडिया की डाइट में कड़कनाथ मुर्गा शामिल करने की सलाह दी है।

- कड़कनाथ मुर्गा कम कोलेस्ट्राल, कम फैट और अधिक प्रोटीन होने की वज़ह से दुनिया भर में जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इसे 'कालामासी' भी कहा जाता है।
- कड़कनाथ मुर्गे का गोश्त उत्कृष्ट औषधीय गुणों के लिये भी प्रसिद्ध है।

- पिछले कुछ समय से कड़कनाथ की मार्केटिंग के प्रयास किये जा रहे हैं।
- 2017 में झाबुआ के कड़कनाथ को जीआई टैग (Geographical Indication) मिला था। 2017 में ही राज्य सरकार ने कड़कनाथ एप भी जारी किया था।
- ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ ने भी दंतेवाड़ा जिले में कड़कनाथ मुर्गे के लिये जीआई टैग का दावा किया था।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI)

- एक भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग की चाय, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू कुछ प्रसिद्ध GI टैग हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है।
- जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं- कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, इत्यादि।

एकल खिड़की हब 'परिवेश'

- 'परिवेश' (PARIVESH: Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub) को राज्य सरकारें 15 जनवरी तक शुरू कर देंगी।
- परिवेश स्कीम केंद्र स्तर पर शुरू की जा चुकी है और राज्यों ने भी इसे 15 जनवरी तक शुरू करने की योजना बना ली है। इस स्कीम को सबसे पहले गुजरात में शुरू करने की योजना है।

क्या है परिवेश?

- 'परिवेश' को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था जो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली हेतु एकल खिड़की सुविधा है।
- प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया है।

- इसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के विचार को भी शामिल किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय, नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है।
- केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिये (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियाँ) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।

- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC), नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित किया है।
- 'परिवेश' की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिये एकल पंजीयन है।

पांडा बॉण्ड (Panda Bond)

पाकिस्तान की कैबिनेट ने चीन के पूँजी बाज़ारों से ऋण लेने के लिए पहली बार रेनमिम्बी मुद्रा बॉण्ड जारी करने को मंज़ूरी दे दी है।

- इस फैसले के ज़रिये पाकिस्तान ने चीन की मुद्रा रेनमिम्बी (RENMINBI) को अमेरिकी डॉलर के बराबर का दर्जा देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है।
- पाकिस्तान का उद्देश्य इस बॉण्ड के ज़रिये चीन के पूँजी बाज़ार से 500 मिलियन से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि एकत्र करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) दोनों ने पहली बार अक्तूबर 2005 में एक ही दिन दो पांडा बॉण्ड (Panda Bond) जारी किये थे।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana)

रोज़गार सृजन के लिये सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना 'प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना' (PMRPY) ने 14 जनवरी, 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित कर कीर्तिमान स्थापित किया है।

- PMRPY की घोषणा 07 अगस्त, 2016 को की गई थी और उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization-EPFO) के ज़रिये श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) लागू कर रहा है।
- योजना के तहत सरकार नियोक्ता (employer) के योगदान का पूरा 12 प्रतिशत का भुगतान कर रही है।
- इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund) और कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme) दोनों शामिल हैं।
- सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिये है, जिन्हें EPFO में 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये तक है।

'वन फैमिली, वन जॉब' योजना ('One Family, One Job' Scheme)

हाल ही में सिक्किम में **'एक परिवार, एक नौकरी/वन फैमिली, वन जॉब'** योजना शुरू की गई है।

- इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक उस परिवार के एक सदस्य को रोज़गार दिया जाएगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है।
- इसके अंतर्गत खेती और कृषि संबंधी सभी ऋण भी निरस्त कर दिये जाएंगे।
- वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के 12 विभागों में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों के लिये भर्तियाँ की जा रही हैं।

श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना की शुरुआत

हाल ही में श्रम मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना 15 फरवरी, 2019 से शुरू कर दी जाएगी।

- श्रम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिये असंगठित क्षेत्र के कामगार 15 फरवरी से सदस्यता ले सकेंगे।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी।
- 15 हज़ार रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामकारों के लिये **प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना** शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- इसके तहत कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र से 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त की जा सकेगी।
- 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपए प्रतिमाह का अंशदान 60 वर्ष की उम्र तक करना होगा।
- 18 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ 55 रुपए प्रतिमाह का अंशदान करना होगा।
- सरकार हर महीने कामगार के पेंशन खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी।
- इस योजना के लिये 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसे वर्तमान वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

उज्ज्वला उत्सव

07 फरवरी 2019 को तेल उद्योग ने 'उज्ज्वला उत्सव' मनाया। यह उत्सव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Prime Minister Ujjwala Yojana -PMUY) की अपार सफलता में शामिल सभी हितधारकों यथा- ज़िला नोडल अधिकारियों, नीति निर्माताओं, वितरकों और लाभार्थियों की भूमिका की सराहना के लिये मनाया गया।

- केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री एवं सचिव तथा तीन तेल विपणन कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों द्वारा तीन राज्यों में एलपीजी के प्रसार में तीन शीर्ष कार्य प्रदर्शन करने वालों को मान्यता दी गई है और संबंधित तेल विपणन कंपनियों के प्रभारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
- ग्राम स्वराज अभियान तथा पूरे देश में 50,000 से अधिक गाँवों में विस्तारित ग्राम अभियान में सराहनीय कार्य के लिये शीर्ष 24 ज़िला नोडल अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
- इस मौके पर गायक कैलाश खेर द्वारा कंपोज़ किया गया PMUY-गीत 'उज्ज्वला भारत उज्ज्वला' लॉन्च किया गया।

पोलावरम परियोजना

हाल ही में आंध्र प्रदेश की **पोलावरम परियोजना (Polavaram Project)** ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज़ कराया। इसके तहत 24 घंटों में 32,100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालने का कार्य किया गया।

- इस परियोजना ने 21,580 क्यूबिक मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया जो अब्दुल वाहेद बिन शबीब (Wahed Bin Shabib), आर.ए.एल.एस कॉन्ट्रैक्टिंग एल.एल.सी (RALS Contracting LLC) और अल्फा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट (Alfa Eng. Consultant) द्वारा वर्ष 2017 में हासिल किया गया था।
- पोलावरम परियोजना के प्रमुख कार्यों को निष्पादित करने के लिये अनुबंधित एजेंसी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (Navayuga Engineering Company Ltd-NECL) ने इस काम को पूरा किया।

परियोजना के बारे में

- वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पोलावरम परियोजना (जिसे **इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना** के नाम से भी जाना जाता है) एक बहुद्देशीय परियोजना है।
- यह परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी ज़िले के पोलावरम मंडल के रम्मय्यापेट (Ramayampet) के निकट **गोदावरी नदी** पर स्थित है।
- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा ज़िलों में सिंचाई, जल विद्युत सुविधा विकसित करने और पेयजल सुविधाएँ प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है।

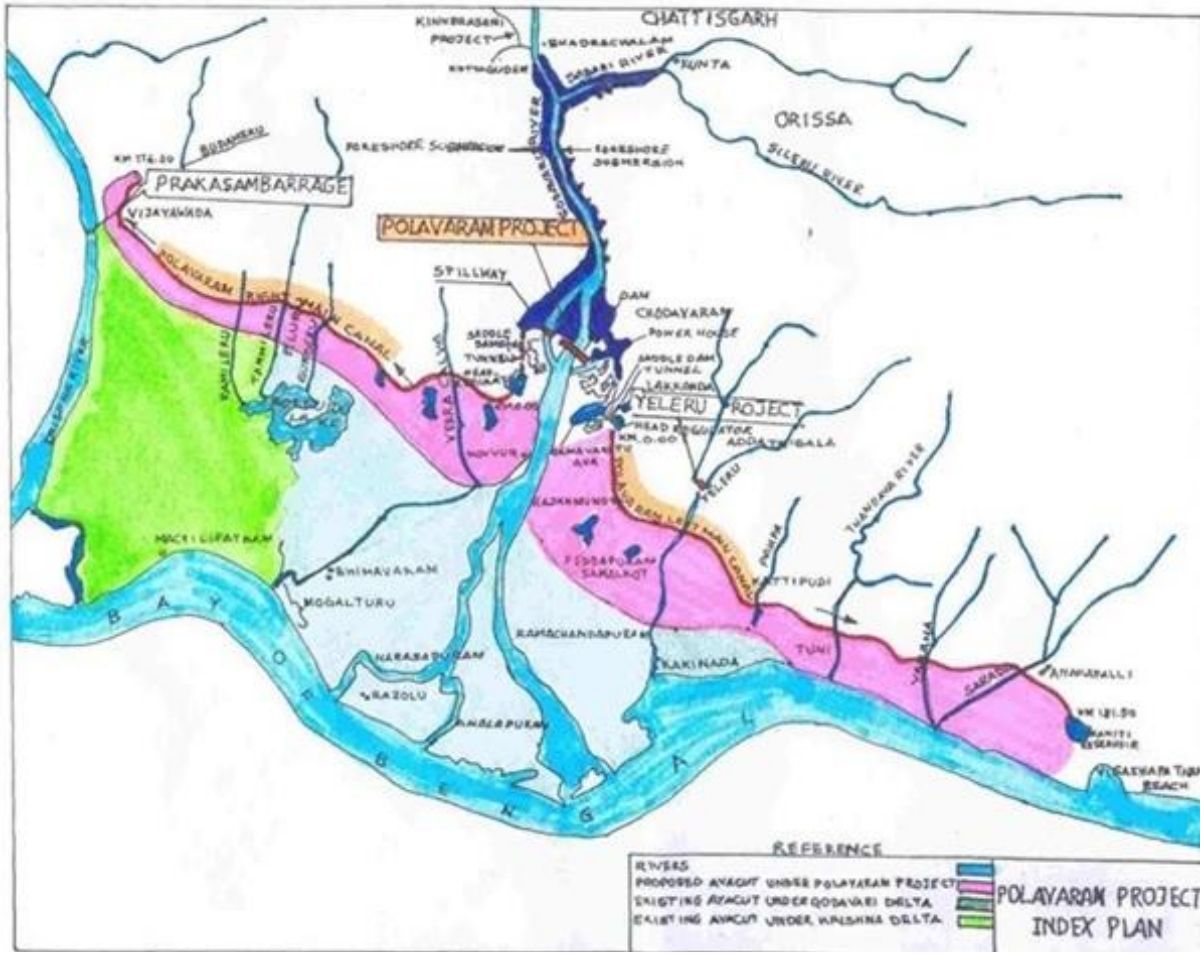

- सरकार ने इस परियोजना को **राष्ट्रीय परियोजना** का दर्जा दिया है और इस पर होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पर्यावरण (Environment)

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) कोष

- क्वांटम सलाहकारों के साथ साझेदारी में टाटा समूह के तीन पूर्व अधिकारी 1 बिलियन डॉलर का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environment, Social and Governance-ESG) कोष जारी करेंगे।
- यह कोष उन भारतीय कंपनियों में निवेश करेगा जो पर्यावरण, समाज और कॉर्पोरेट प्रशासन को महत्त्व देते हों।
- प्रस्तावित संयुक्त उद्यम लंबी अवधि के उन विदेशी निवेशकों, जैसे- पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और हाई नेटवर्थ इंडिविज़ुअल (High Networth Individuals-HNIs) से धन जुटाएगा जो पर्यावरण, समाज और कॉर्पोरेट प्रशासन को महत्त्व देते हैं।

बायो-जेट ईंधन के लिये नया मानक

- सभी सैन्य और नागरिक विमानों में **बायो-जेट ईंधन** का उपयोग करने के लिये BIS ने IAF, अनुसंधान संगठन और उद्योग के साथ मिलकर विमानन टर्बाइन ईंधनों हेतु एक नया मानक पेश किया है।
- BIS द्वारा उल्लिखित ये विशेष मानक भारतीय मानकों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे।
- इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित एक समिति को आवश्यक मानक तैयार करने का काम सौंपा गया था।
- विचार-विमर्श के बाद भारतीय मानक IS 17081:2019 विमानन टर्बाइन ईंधन (केरोसिन टाइप, जेट A-1) तैयार किया गया है जिसमें सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन शामिल हैं।
- यह मानक तेल कंपनियों को भारतीय विमानन उद्योग के लिये बायो-जेट ईंधन बनाने में सक्षम करेगा।
- इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (International Civil Aviation Organisation-ICAO) द्वारा 2027 तक कार्बन ऑफ़सेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA) के आगमन को देखते हुए, यह एक महत्त्वपूर्ण विकास है जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है और भारत को एक हरित ईंधन उत्पादन केंद्र बनने में मदद कर सकता है।

काजीरंगा के दो गैंडों को मिला नया घर (Two Rhinos of Kaziranga Find a New Home)

हाल ही में दो गैंडों (Rhinos), जो वर्ष 2016 में **काजीरंगा नेशनल पार्क** में आई बाढ़ के कारण विस्थापित हो गए थे, को मानस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है।

- उल्लेखनीय है कि जब ये गैंडे विस्थापित हुए थे तब बहुत ही छोटे थे। इन दोनों को काजीरंगा के वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र (Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation-CWRC) में एक साथ रखा गया था।
- वर्ष 2002 में CWRC की शुरुआत के बाद से विभिन्न कारणों से काजीरंगा नेशनल पार्क के जंगलों में फँसे 50 से अधिक गैंडों के बच्चों को बचाया जा चुका है, इनमें से अधिकांशत: ऐसे थे जो बाढ़ के कारण विस्थापित हो गए थे।
- वर्तमान में मानस नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या 38 है।
- मानस नेशनल पार्क में गैंडों का संवर्द्धन **'ब्रिंग बैक मानस, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट' (Bring Back Manas, A UNESCO World Heritage Site)** नामक पहल का हिस्सा था।

मानस नेशनल पार्क

- अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य से भरा मानस नेशनल पार्क, असम राज्य में भूटान-हिमालय की तलहटी में स्थित है।
- यह वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत बाघ अभयारण्यों के नेटवर्क में शामिल होने वाले प्राथमिक अभयारण्यों में से एक है।
- वर्ष 1985 में यूनेस्को (UNESCO) ने मानस वन्यजीव अभयारण्य को विश्व विरासत स्थल (World Heritage Site) का दर्ज़ा प्रदान किया था।
- विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के सात साल बाद ही इस अभयारण्य को 'खतरनाक' घोषित कर दिया गया था लेकिन वर्ष 2011 में IUCN तथा यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति की सलाह के बाद इसे 'खतरनाक' अभयारण्यों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था।
- वर्ष 1989 में इसे बायोस्फीयर रिज़र्व (Biosphere Reserve) तथा वर्ष 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया।

उभयचरों की 19 प्रजातियाँ गंभीर रूप से लुप्तप्राय (19 species of amphibians are critically endangered)

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI) ने भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची जारी की है।

- ZSI के वैज्ञानिक 2009 से ही अन्य संस्थानों के साथ मिलकर समय-समय पर भारतीय उभयचरों की सूची को अद्यतन करते रहे हैं।

- सूची में उन प्रजातियों का उल्लेख भी किया गया है जो प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Union for Conservation of Nature-IUCN) के अनुसार अगर खतरे में हैं।
- ZSI की वर्तमान सूची में भारत की 432 उभयचर प्रजातियों के नाम, खोज का वर्ष और IUCN की रेड लिस्ट में उनके संरक्षण को दर्ज किया गया है।
- सूचीबद्ध उभयचरों में 19 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना गया, जबकि 33 प्रजातियों को संकटग्रस्त माना गया है।
- सूची में 19% उभयचरों को ऐसी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनके बारे में डेटा अपर्याप्त है और 39% प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन IUCN द्वारा नहीं किया गया है।

IUCN की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक संकेतक है।
- IUCN के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत उभयचरों के विलुप्त होने का खतरा है।
- IUCN के अनुसार, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ वे हैं जो जंगलों से विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं।

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI)

- समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना तत्कालीन 'ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य' में 1 जुलाई, 1916 को की गई थी।
- इसका उद्भव 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था।

फ्लेमिंगो महोत्सव (Flamingo Festival)

तीन दिवसीय वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव पुलिकट झील (Pulicat lake) और सुल्लुरपेटा (Sullurpeta) मंडल के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य (Nelapattu Bird Sanctuary) में आयोजित किया जाता है।

- इस महोत्सव का उद्देश्य पुलीकट और नेलापट्टू में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- विभिन्न प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिये सर्दियों कै मौसम के दौरान इस स्थान पर आते हैं।
- आमतौर पर पक्षियों की लगभग 80 अलग-अलग प्रजातियाँ प्रजनन के लिये पुलीकट में प्रवास करती हैं।
- इस वर्ष 90,000 से भी अधिक प्रवासी पक्षी दूर-दूर से पुलीकट झील में आए हैं।

नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य

- नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भारत में सबसे लोकप्रिय पक्षी अभयारण्यों में से एक है।
- दक्षिण पूर्व एशिया में पेलिकन के लिये सबसे बड़े निवास स्थान के रूप में लोकप्रिय नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कई अन्य मूल तथा प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है।
- पुलीकट वन्यजीव विभाग ने वर्ष 1976 में इस पक्षी अभयारण्य की स्थापना की थी।
- इसका क्षेत्रफल 458.92 हेक्टेयर है।
- यह आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा पर पुलिकट झील के उत्तर में लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित है।

भारत में प्रवासन करने वाले पक्षी

भारत में प्रवासन करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पक्षी	शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पक्षी
एशियाई कोयल (Asian Koel) काले ताज वाला रात्रि बगुला (Black crowned night heron) यूरेशियन गोल्डन ओरियलकॉम्ब बत्तख ब्लू-चिक्ड बी-ईटर (Blue-cheeked Bee-Eater) ब्लू-टेल्ड् बी-ईटर सारंग (Cuckoo)	आमुर फाल्कन साइबेरियन क्रेन ग्रेटर फ्लेमिंगो रफ (Ruff) काले पंखों वाला स्टिल्ट (Black winged stilt) कॉमन टील (Common Teal) कॉमन ग्रीनशेंक (Common Green shank) उत्तरी पिनटेल (Northern Pintail) पीला वेग्टेल (Yellow wagtail) सफेद वेग्टेल (White wagtail) उत्तरी शोवेलर (Northern Shoveler) स्पॉटेड सेंडपाइपर यूरेशियन वाइगन चित्तीदार रेडशेंक (Spotted Redshank)

पुलीकट झील

यह भारत में आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश से उत्तरी तमिलनाडु के बीच लगभग 80 किमी. के क्षेत्रफल में फैली हुई है।

- पुलिकट झील, जिसे तमिल में पजहवेर्कादु एरी कहते हैं खारे पानी की झील है।
- ओडिशा में चिल्का झील के बाद यह झील देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
- यह झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है।
- बंगाल की खाड़ी से यह झील श्रीहरिकोटा द्वारा अलग होती है जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है।

'सक्षम 2019' (Saksham 2019)

16 जनवरी, 2019 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) के तत्त्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association-PCRA) के वार्षिक जनकेंद्रित अभियान **'सक्षम 2019'** की शुरुआत की गई।

- इसके लिये PCRA तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसिद्ध तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा एक माह तक चलने वाले कार्यक्रम 'सक्षम 2019' के दौरान विभिन्न संवादमूलक कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
- सक्षम का पूरा नाम **संरक्षण क्षमता महोत्सव** (Sanrakshan Kshamata Mahotsav) है।
- इस अभियान की टैगलाइन - **इंधन संरक्षण की ज़िम्मेदारी, जन गण की भागीदारी** (Indhan Sanrakshan Ki Jimmedari, Jan Gan Ki Bhagidari) है।

PCRA

- पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है।
- गैर-लाभकारी संगठन के रूप में PCRA एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने में कार्यरत है।
- यह तेल की आवश्यकता के संदर्भ में देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियाँ एवं रणनीतियाँ प्रस्तावित करने में सरकार की सहायता करता है।

---

687 परियोजनाओं में से 682 को मंज़ूरी

- पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife-NBWL) ने संरक्षित क्षेत्रों की वन भूमि को उद्योग हेतु मंज़ूरी प्रदान करते हुए 687 परियोजनाओं में से 682 (99.82%) को मंज़ूरी दे दी।

सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ

- 2014 के बाद से नियमित बैठकें
- ऑनलाइन आवेदन
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में वही परियोजनाएँ आती हैं जिनकी जाँच संबंधित राज्य सरकार पहले ही कर चुकी होती है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन 2003 में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर किया गया था।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
- यह निकाय वन्यजीवन संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिये और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों एवं इसके आस-पास परियोजनाओं की मंज़ूरी हेतु एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निकाय है क्योंकि यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा आस-पास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की संरचना के तहत इसमें 15 अनिवार्य सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्यों को रखने का प्रावधान है।

तीसरा भारत- जर्मन पर्यावरण सम्मेलन (Third Indo-German Environment Forum-IGEnvF)

13 फरवरी, 2019 को तीसरे भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

- इस सम्मेलन की **थीम 'स्वच्छ वायु, हरित अर्थव्यवस्था' (Cleaner Air, Greener Economy)** थी।
- इस एक दिवसीय सम्मेलन में सामूहिक विचार-विमर्श और सामानांतर अधिवेशनों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन की चुनौतियों, समाधानों और आवश्यक कार्यक्रमों के साथ-साथ क्रमश: **पेरिस समझौते (Paris Agreement)** तथा **संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 (Agenda 2030 of UN)** पर आधारित NDCs (**राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान**) और **सतत् विकास लक्ष्यों** (Sustainable Development Goals-SDGs) के कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया गया।
- इस सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने ज़र्मन बिज़नेस की एशिया-प्रशांत समिति और फिक्की के सहयोग से किया।
- सम्मेलन में मंत्रालयों, कारोबार एवं विज्ञान जगत के साथ-साथ विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की।
- इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच स्वच्छ वायु और वस्त्र क्षेत्र के लिए संदर्भ की तैयारी के बारे में दो संयुक्त आशय घोषणापत्रों (Joint Declaration of Intent-JDI) का भी आदान-प्रदान किया गया।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary-WWS)

नीलगिरि के जैवमंडल (Nilgiri Biosphere) में पारे के ऊपर चढ़ने के साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु के वन्यजीव अभयारण्यों से वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary-WWS) में जंगली जानवरों का मौसमी प्रवास शुरू हो गया है।

- यह अभयारण्य केरल के वायनाड ज़िले में स्थित है जहाँ कर्नाटक के बांदीपुर (Bandipur) और नागरहोल (Nagarhole) राष्ट्रीय उद्यानों तथा तमिलनाडु के मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान (Mudumalai National Park) से हाथी और गौर (Gaur) जैसे स्तनधारी भोजन और पानी की तलाश में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की ओर पलायन करते हैं।
- इस अभयारण्य में जानवरों के आने का प्रमुख कारण गर्मियों के दौरान भोजन और पानी की आसान उपलब्धता है।
- 1973 में स्थापित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर-पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु का मुदुमलाई संरक्षित क्षेत्र इसके समीपवर्ती क्षेत्र (contiguous area) हैं।
- जैव विविधता से समृद्ध, अभयारण्य नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व (Nilgiri Biosphere Reserve) का एक अभिन्न अंग है, जिसे क्षेत्र की जैविक विरासत के संरक्षण के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

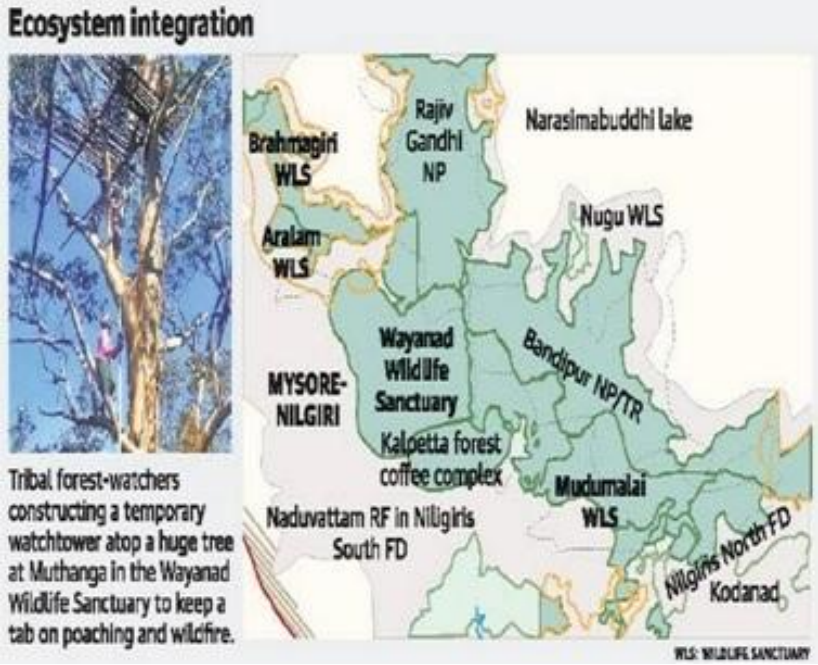

चक्रवात 'पाबुक'

हाल ही में चक्रवात 'पाबुक' ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर दस्तक दी।

- इस चक्रवात की उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुई है।
- यह तूफान अंडमान सागर और उसके आसपास मंडराता रहा है।
- केंद्र सरकार ने चक्रवाती तूफान की चपेट में आए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।
- 'ऑरेंज' अलर्ट मौसम संबंधी एक चेतावनी होती है, जो चक्रवात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाले खतरों के स्तर को इंगित करता है।
- 'ऑरेंज' अलर्ट खराब या अत्यंत खराब मौसम के बारे में लोगों को सावधान रहने की चेतावनी है।
- इस अलर्ट के तहत सड़क और हवाई यात्रा बाधित हो सकती है साथ ही जीवन और संपत्ति को भी खतरा हो सकता है।

6ठा 'भारतीय महिला जैविक उत्सव'

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चंडीगढ़ के लेजर वैली में 12 से 14 जनवरी, 2019 तक छठे **'भारतीय महिला जैविक उत्सव'** की मेज़बानी करेगा।
- इसका उद्देश्य भारत के दूरदराज़ के इलाकों में जैविक क्षेत्र से संबंधित महिला किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
- लेजर वैली में 100 से अधिक महिलाएँ शरीक होंगी और यह जैविक महोत्सव का केंद्र बनेगा।
- इस उत्सव में एक हज़ार से अधिक विभिन्न जैविक उत्पाद पेश किये जाएंगे, जिनमें वस्त्र, आरोग्यकारी, अनाज, बीज, आभूषण, बेकरी उत्पाद इत्यादि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला जैविक उत्सव 2015 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है।

सिनेरियस गिद्ध

हाल ही में झारखंड के हजारीबाग में दो सिनेरियस गिद्ध (Aegypius monachus-एजिपियस मोनाशस) देखे गए।

- **एजिपियस मोनाशस लैटिन भाषा से लिया गया नाम है जिसका तात्पर्य 'हूड वाला' होता है।**
- **आमतौर पर सर्दियों के दौरान काले रंग व गुलाबी चोंच वाला यह सिनेरियस गिद्ध (Cinereous vulture) यूरोप और एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों से भारत जैसे गर्म स्थानों में पलायन करता है।**

- **इस प्रवासी पक्षी के बारे में ज्ञात रिकॉर्ड से पता चला है कि यह भारत के उत्तरी हिस्सों में राजस्थान तक आता है लेकिन झारखंड के हजारीबाग में इसे देखा जाना बर्ड वॉचर्स और शोधकर्त्ताओं को चौंकाने वाला है।**
- **सिनेरियस गिद्ध को IUCN की लाल सूची में निकट-संकट (Near Threatened या NT) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- **भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इन पक्षियों की आबादी घटती जा रही है। भारत ने देश के कई हिस्सों में प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनके संरक्षण की योजना शुरू की है।**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

गगनयान के लिये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित

हाल ही में इसरो (Indian Space Research Organisation-ISRO) द्वारा अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष **मिशन गगनयान** के लिये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (Human Space Flight Centre-HSFC) का अनावरण किया गया।

- मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) गगनयान परियोजना के क्रियान्वयन से संबद्ध है, इसकी गतिविधियों में अंतरिक्ष में चालक दल के लिये इंजीनियरिंग सिस्टम का विकास, चालक दल का चयन और प्रशिक्षण और कार्यक्रम की निगरानी शामिल है।
- 2019 में इसरो के लिये गगनयान 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है, इस योजना के अंतर्गत पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में तथा दूसरा जुलाई 2021 तक भेजने की संभावना है।
- इसरो के इस अभियान में एक महिला अंतरिक्ष यात्री के शामिल होने की संभावना है।

गगनयान मिशन

अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन **गगनयान** को भेजने के लिये इसरो ने लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस मिशन के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार किया है।
- गगनयान कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिये इसरो ने बंगलूरू के अपने मुख्यालय में **'मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र'** (Human Space Flight Centre) भी स्थापित किया है। उन्नीकृष्णन नायर (Unnikrishnan Nair) को इस केंद्र के निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

इसरो की योजना-

- दिसंबर 2020 में गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित (बिना अंतरिक्ष यात्री वाला) यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
- इसके बाद जुलाई 2021 में दूसरा मानव रहित यान भेजा जाएगा।
- दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान मिशन भेजा जाएगा।

नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन

- हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC ने दो दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेज़बानी की। इस सम्मेलन की थीम 'टेक्नोलॉजीज़ फॉर नेक्स्टजेन गवर्नेंस' (Technologies for NextGen Governance) थी।
- इस सम्मेलन में बिग डेटा और एडवांस्ड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेवऑप्स (DevOps)/एज़ाइल मेथडोलॉजी, क्लाउड नेटिव स्केलेबल एप्लिकेशन, माइक्रो-सर्विसेज़, सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center-NIC)

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से यह ई-सरकार/ई-शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक 'प्रमुख निर्माणकर्ता' के रूप में उभरने के साथ-साथ सतत् विकास के लिये डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है।
- NIC ने अपने आईसीटी नेटवर्क 'निकनेट' के जरिये केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 36 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और भारत के 708 ज़िला प्रशासन के साथ संस्थागत रूप संबंध स्थापित किया है।

संचालित की जा रही प्रमुख गतिविधियाँ:

- आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उत्पादों का कार्यान्वयन
- सरकारी विभागों के लिये परामर्श कार्य
- अनुसंधान एवं विकास और
- क्षमता निर्माण

सुपर ब्लड वुल्फ मून (Super Blood Wolf Moon)

20-21 जनवरी, 2019 को दुनिया के कई हिस्सों में **सुपर ब्लड वुल्फ मून** (एक पूर्ण चंद्र ग्रहण) दिखाई दिया।

- यह उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देखा गया। लेकिन यह पूर्ण चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया।
- सुपर ब्लड वुल्फ मून एक चंद्र ग्रहण है जिसकी अवधि लगभग 62 मिनट तक थी। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि सूरज की किरणें पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती हैं। पृथ्वी की छाया में चंद्रमा का रंग बदलकर लाल हो जाता है।
- इस सुपर ब्लड मून को **सुपर ब्लड वुल्फ मून** कहा जाता है क्योंकि कई संस्कृतियों में साल की पहली पूर्णिमा को वुल्फ मून के रूप में नामित किया गया है।

चंद्रग्रहण से संबंधित शब्दावलियाँ

- **चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse):** जब कभी चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुज़रता है, तो उसे चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है।
- **सुपर मून (Super Moon):** सुपर मून के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके परिमाणस्वरुप चंद्रमा आकार में 7% बड़ा और 15% अधिक चमकीला दिखाई देता है।
- **ब्लड मून (Blood Moon):** जब चंद्रमा का रंग गहरा लाल हो जाता है तो उसे ब्लड मून कहते हैं। नासा (NASA) के अनुसार, यह रंग वातावरण में धूल और बादलों की मात्रा पर निर्भर करता है।
- **ब्लू मून (Blue Moon):** जब एक ही कैलेंडर महीने में दो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो दूसरे को "ब्लू मून" कहा जाता है

शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड' (Shooting Stars On Demand)

हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार कृत्रिम उल्का पिंडो की आतिशबाजी कराने के लिये तैयार किये गए एक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल की है।

- इसमें छोटे आकार के एप्सिलॉन-4 (Epsilon-4) रॉकेट की सहायता से जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (Japan Aerospace Exploration Agency-JAXA) के यूशीनौरा (Uchinoura) अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया ।
- इसके प्रारंभिक प्रयोग को **'शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड'** नाम दिया गया है।
- यह उपग्रह ऐसे छोटे-छोटे गेंद के आकार वाले पदार्थ को अंतरिक्ष में मुक्त करेगा, जो धरती के वातावरण में प्रवेश करने पर ठीक उसी तरह जल उठेंगे जैसे प्राकृतिक उल्का पिंड।
- उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड में मौजूद छोटे-छोटे उल्कापिंड या चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घुसते ही जल जाते हैं, जिससे रोशनी प्रकट होती है और यह आतिशबाजी जैसा प्रतीत होता है।

भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री (India's First Lithium Ion Giga Factory)

भारत में पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री के निर्माण के लिये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited-BHEL) और लिबकॉइन (Libcoin) के बीच वार्ता चल रही है।

- इस संयंत्र की क्षमता 30 GWh (GigaWatt hours) तक बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है।
- यह परियोजना मेड बाई इंडिया, फॉर इंडिया (Made by India, for India) के तहत शुरू की जाएगी। इसके अतंर्गत प्रमुख मशीनों का निर्माण देश में किया जाएगा।

लाभ

- इस परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी तथा तेल आयात में कमी होगी।
- बिजली आधारित परिवहन व्यवस्था से उत्सर्जन में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान पूरे विश्व में बिजली से चलने वाली कारों की संख्या दस लाख तक पहुँच गई है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) ने 2030 तक पूरे विश्व में बिजली चालित कारों की संख्या 140 मिलियन होने का अनुमान लगाया है।

ली-आयन या लिथियम आयन बैटरी

- लिथियम आयन बैटरी (lithium-ion battery या LIB) एक पुन: चार्ज करने योग्य बैटरी होती है।
- ये बैटरियाँ आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में प्राय: उपयोग की जाती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के लिये सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरियों में से एक हैं।
- लिथियम-ऑयन बैटरी के धनाग्र और ऋणाग्र पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस बैटरी का विद्युत अपघट्य, इन विद्युताग्रों के बीच लिथियम ऑयनों के आवागमन के लिये माध्यम प्रदान करता है।

उन्नति (UNNATI) कार्यक्रम

17 जनवरी, 2019 को बंगलूरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) के 'उन्नति' (UNNATI) कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

- उन्नति (UNNATI) का पूरा नाम UNispace Nanosatellite Assembly & Training by ISRO है।
- यह नैनोसैटेलाइट (nanosatellites) विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (capacity building programme) है, जो अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) की 50वीं वर्षगांठ (UNISPACE 50) मनाने के लिये ISRO की एक पहल है जिसकी घोषणा 18 जून, 2018 को वियना में आयोजित संगोष्ठी के दौरान की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1968 में वियना (ऑस्ट्रिया) में किया गया था।
- यह कार्यक्रम विकासशील देशों के प्रतिभागियों को नैनोसैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है।
- UNNATI कार्यक्रम को इसरो के यू.आर.राव सैटेलाइट सेंटर (U.R. Rao Satellite Centre-URSC) द्वारा 3 सालों तक 3 बैचों में संचालित करने की योजना है और इसका लक्ष्य 45 देशों के 90 अधिकारियों को लाभ पहुँचाना है।
- प्रत्येक बैच की अवधि 8-सप्ताह की होगी और इसमें नैनोसैटेलाइट की परिभाषा, उपयोगिता, अंतरिक्ष मलबे पर उनके प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कानून, डिजाइन ड्राइवर्स, विश्वसनीयता और गुणवत्ता आश्वासन तथा नैनोसैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
- इस कार्यक्रम के प्रथम बैच की शुरुआत 17 देशों (अल्ज़ीरिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, भूटान, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्याँमार, ओमान, पनामा और पुर्तगाल) के 30 प्रतिभागियों के साथ की गई है।

विज्ञान संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की पहल (National level initiatives in the field of science communication)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) ने दूरदर्शन (DD), प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों- **'डीडी साइंस' (DD Science)** और **'इंडिया साइंस' (India Science)** की शुरुआत की है।

- भारत में विज्ञान संचार के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले ये दोनों विज्ञान चैनल देश में एक राष्ट्रीय विज्ञान चैनल की शुरुआत करने की दिशा में आरंभिक कदम है।
- इनका **कार्यान्वयन एवं प्रबंधन विज्ञान प्रसार (Vigyan Prasar)** द्वारा किया जा रहा है।
- डीडी साइंस, दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर एक घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस, इंटरनेट आधारित चैनल है, जो किसी भी इंटरनेट आधारित उपकरण पर उपलब्ध है।
- इन दोनों चैनलों के ज़रिये विज्ञान आधारित वृत्तचित्र (Documentaries), स्टूडियो आधारित परिचर्चाओं एवं वैज्ञानिक संस्थानों के आभासी पूर्वाभ्यास, साक्षात्कार और लघु फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ये चैनल दर्शकों के लिये पूरी तरह से निःशुल्क होंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की स्थापना मई 1971 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना और देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और प्रचार के लिये एक केंद्रीय विभाग के रूप में काम करना है।

प्रसार भारती (Prasar Bharti)

- प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया।
- यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक (Public Service Broadcaster) है।
- प्रसार भारती अधिनियम में संदर्भित सार्वजनिक सेवा प्रसारण उद्देश्यों को आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया यूनिट के रूप कार्य करते थे और प्रसार भारती की स्थापना के बाद इसके घटक बन गए थे।

विज्ञान प्रसार (Vigyan Prasar)

- वर्ष 1989 में स्थापित विज्ञान प्रसार (वि.प्र.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है।
- इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यों/गतिविधियों की शुरुआत करना, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और उनका प्रचार-प्रसार करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु संसाधन-सह-सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करना है।

सेना प्रौद्योगिकी सेमिनार (आरटेक-2019) (Army Tech Seminar -ARTECH 2019)

11 जनवरी, 2019 को भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ केंद्र (Manekshaw Centre) में सेना प्रौद्योगिकी सेमिनार-2019 (आरटेक 2019) का आयोजन किया।

- इस सेमिनार की थीम **'युद्ध क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का विध्वंसक प्रभाव' (Disruptive Impact of Emerging Technologies on Land Warfare)** थी।
- सेमिनार का उद्देश्य सैन्य, शिक्षा क्षेत्र और उद्योग से जुड़े साझेदारों के लिये युद्ध पर प्रभाव डालने वाली उभरती प्रौद्योगिकी का स्वरूप उपलब्ध कराना था।

संपन्न (SAMPANN)

हाल ही में दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के लिये एक व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर 'संपन्न' लॉन्च किया गया।

- **संपन्न का पूरा नाम सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ़ पेंशन ((System for Accounting and Management of Pension- SAMPANN) है।**
- **इस डिजिटल सेवा के ज़रिये पेंशनर घर बैठे मोबाइल पर ही अपनी पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।**
- **इस सेवा के माध्यम से दूरसंचार विभाग के पाँच लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि फिलहाल दूरसंचार विभाग के साढ़े तीन लाख पेंशनर लाभ प्राप्त करेंगे तथा बाद में डेढ़ लाख और पेंशनर इससे जुड़ेंगे।**

सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर

हाल ही में नौसेना ने ऐसे कंटेनरों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो समुद्र में परिचालन के दौरान रसद क्षमता को बढ़ाने हेतु सीधे हवाई जहाज से गिराए जा सकते हैं।

- **50 किलोग्राम के पेलोड के साथ परीक्षण हेतु हवाई जहाज से अरब सागर में गिराया गया। पुर्जों से लैस इस कंटेनर को तट से 2,000 किमी. दूर समुद्र में स्थित जहाजों के लिये डिज़ाईन किया गया है।**

- **गोवा के तट से एक IL-38 विमान द्वारा इस 'सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर' का सफल परीक्षण किया गया है।**
- **यह बेलनाकार कंटेनर स्वदेशी है जिसे नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (Naval Science & Technological Laboratory-NSTL)) तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है।**

नासा ने की नए ग्रह की खोज

हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। गौरतलब है कि यह सफलता नासा के ग्रह खोजी अभियान को मिली है।

- नासा द्वारा खोजे गए इस ग्रह का नाम HD 21749b है।
- पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष दूर यह ग्रह रेटीकुलम तारामंडल के सूर्य के समान चमकीले ड्वार्फ (बौने) तारे का चक्कर लगा रहा है।
- तारे से नज़दीक होने के बाद भी इस HD 21749b नामक ग्रह की सतह का तापमान 300 डिग्री फारेनहाइट ही है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी के कारण इसका वायुमंडल घना है और इस पर जीवन की संभावना भी हो सकता है।
- यह ग्रह पृथ्वी से तीन गुना बड़ा और 23 गुना भारी है। इस ग्रह को सब-नेपच्यून (Sub-Neptune) वर्ग में रखा गया है।
- इस ग्रह का ज़्यादातर हिस्सा गैसीय है और इसका वायुमंडल नेपच्यून (Neptune) और यूरेनस (Uranus) से भी घना है।
- नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite-TESS) मिशन द्वारा खोजा गया यह तीसरा ग्रह है।

TESS मिशन

- नासा ने इस मिशन को पिछले साल 16 अप्रैल, 2018 को लॉन्च किया था। अगस्त में इसने पहली तस्वीर भेजी थी। नासा के इस मिशन के तहत सौरमंडल के बाहरी ग्रहों यानी एक्सोप्लेनेट की खोज की जानी है।

भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का 106वाँ अधिवेशन (106th Session of Indian Science Congress)

- 3 से 7 जनवरी, 2019 तक जालंधर (पंजाब) के **लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी** (Lovely Professional University-LPU) में **भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के 106वें अधिवेशन का आयोजन किया गया।**
- इस अधिवेशन की थीम **'भविष्य का भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी'** (Future India: Science and Technology) थी।
- भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के हिस्से के रूप में महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस (Women's Science Congress) तथा चिल्ड्रेंस साइंस कॉन्ग्रेस (Children's Science Congress) का भी आयोजन किया गया।
- इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने **'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान'** का नारा भी दिया।
- इस वैज्ञानिक सम्मेलन में पंद्रह हज़ार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी **'प्राइड ऑफ इंडिया'** (Pride of India) भी आयोजित की गई, जिसमें DRDO, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, CSIR, ICAR, ICMR, NPCIL और विभिन्न वैज्ञानिक विभागों और विश्वविद्यालयों सहित 150 संगठनों ने भाग लिया।

- प्रवेश द्वार पर स्थापित 55 फीट ऊँचा और 25 टन वज़न का **'मेटल मैग्ना'** (Metal Magna) नामक रोबोट मुख्य आकर्षण था।
- 105वें भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन 16 से 20 मार्च, 2018 के मध्य मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल (मणिपुर) में किया गया था।

चीन का लूनर रोवर युतु-2

हाल ही में चीन ने चंद्रमा के अनदेखे हिस्से के बारे में जानकारी जुटाने के लिये चांग ई-4 यान का प्रक्षेपण किया।

- चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3 रॉकेट के ज़रिये यह प्रक्षेपण किया गया था।
- चांग ई-4 का उद्देश्य चंद्रमा के उस हिस्से के रहस्यों का खुलासा करना है, जहाँ अभी तक कोई यान नहीं गया है।

- ध्यातव्य है कि चंद्र अभियान 'चांग ई-4' का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है।
- चीनी मीडिया के मुताबिक, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले खोजी रोवर का नाम युतु-2 होगा।
- युतु-2 रोवर, चंद्र अभियान 'चांग ई-4' का ही एक हिस्सा है।

'मदर ऑफ ऑल बॉम्स'

- हाल ही में चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, जिसे आधिकारिक मीडिया द्वारा "मदर ऑफ ऑल बॉम्स" कहा जा रहा है।
- अब तक दुनिया के सामने अमेरिका के 'मदर ऑफ ऑल बॉम्स' और रूस के 'फादर ऑफ ऑल बॉम्स' ही थे, लेकिन चीन ने अपने इस बम को दोनों से ज़्यादा खतरनाक बताया है।

- चीन का दावा है कि किसी भी परमाणु हथियार के बाद यह बम दूसरा सबसे ज़्यादा घातक हथियार है।

- मदर ऑफ ऑल बॉम्स का चीनी संस्करण अमेरिकी बम से छोटा (छह मीटर) और हल्का है, लेकिन इससे मचने वाली तबाही खतरनाक है।

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

रोशनी एप (Roshni App)

दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से करेंसी नोटों के मूल्य निर्धारण में सहायता के लिये **'रोशनी' (Roshni)** नामक **एंड्रॉइड एप** विकसित किया गया है।

- इस एप को पंजाब के **रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology)** ने विकसित किया है।
- इसको विकसित करने के लिये इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का उपयोग किया गया है।
- रोशनी पहला एंड्रॉइड एप है जो विमुद्रीकरण के बाद चलन में आए नए नोटों की सफलतापूर्वक पहचान कर सकता है।
- यह एप एक रूपांतरणीय तथा गहन अध्ययन करने में सक्षम संरचना का उपयोग करता है, जो आगे चलकर नोटों पर बने अलग-अलग पैटर्न और विशेषताओं का उपयोग कर अलग-अलग मूल्य के नोटों में अंतर स्थापित करता है।
- संस्थान की IPSA (इमेज प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स) लैब ने विभिन्न मुद्रा नोटों की 13, 000 से अधिक छवियों का एक समृद्ध डेटासेट तैयार किया।
- इसमें उपयोगकर्त्ता को करेंसी नोट को फोन के कैमरे के सामने लाना होगा और एप ऑडियो अधिसूचना के ज़रिये उपयोगकर्त्ता को करेंसी नोट के मूल्य के बारे में बताएगा।
- इसके अलावा Microsoft द्वारा विकसित Seeing AI एकमात्र एप है जो पुराने और नए दोनों प्रकार के भारतीय नोटों की पहचान करता है।

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)

17 जनवरी, 2019 को मुंबई में **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS)** पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- इस क्षेत्रीय सम्मलेन में देश के पश्चिमी क्षेत्र की कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (Programme Implementing Agencies-PIAs) ने भाग लिया।
- इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन संशोधित योजना के प्रावधानों का प्रसार करने और कार्यान्वयन एजेंसियों को विभाग के संपर्क में लाने के लिये किया गया था।
- इस सम्मेलन ने केंद्र सरकार से लेकर कार्यान्वयन एजेंसियों तक सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया।
- DDRS भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है जो वर्ष 1999 से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिये काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये लागू की गई है।
- इस योजना को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू है।

स्वच्छ शक्ति -2019 (Swachh Shakti-2019)

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन किया।

- स्वच्छ शक्ति का यह तीसरा सम्मेलन था जिसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया।
- स्वच्छ शक्ति-2019 एक राष्ट्रीय आयोजन है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डालना है।
- इस आयोजन में पूरे देश की महिला सरपंच और पंच शामिल हुईं।
- इस वर्ष महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से लगभग 15,000 महिलाओं ने स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में भाग लिया है।

- इस कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंचों द्वारा स्वच्छ भारत के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर अपनाई गई बेहतरीन पद्धतियों को साझा किया जाता है।
- इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत की उपलब्धियों और हाल ही में आयोजित स्वच्छ सुंदर शौचालय, (Neat and Clean Toilet) जो कि विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है का भी पहली बार इसमें प्रदर्शन किया गया।

पृष्ठभूमि

- स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में गुजरात के गांधीनगर से हुई थी। तब देश भर से 6 हज़ार महिला सरपंचों ने इसमें भाग लिया था।
- दूसरे स्वच्छ शक्ति सम्मेलन का आयोजन 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। जिसमें 8 हज़ार महिला सरपंच, 3 हज़ार महिला स्वच्छाग्रही तथा देश भर में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था।
- स्वच्छ भारत अभियान के क्षेत्र में किये गए सराहानीय कार्यों के लिये इन महिलाओं को सम्मानित किया गया था।

WebWonderWomen

- हाल ही में मानवाधिकार संगठन ब्रेकथ्रू के साथ साझेदारी में ट्विटर इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने #WebWonderWomen अभियान की शुरुआत की है।
- #WebWonderWomen ऐसी महिलाओं की पहचान करने, उनका सम्मान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का अभियान है जो अपनी क्षमता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

- इस अभियान के तहत लोग दुनिया में कहीं भी, अपनी पसंदीदा भारतीय महिला एचीवर को अपने ट्विटर हैंडल से नामांकित कर सकते हैं।
- महिलाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में नामित किया जा सकता है- स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य, कला, खेल, तकनीक, यात्रा, व्यवसाय, कानूनी / नीति, सरकारी, मनोरंजन, फैशन / सौंदर्य, वित्त, खाद्य और पर्यावरण।

लद्दाख की दर्द आर्यन जनजाति (Ladakh's Dard Aryan Tribes)

लद्दाख के दर्द आर्यन जनजाति ने केंद्र सरकार से अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

- **दर्द आर्यन जनजाति जो अपनी उदार परंपराओं के लिये जानी जाती है, को आर्यों का वंशज माना जाता है।**
- **कई शोधकर्त्ताओं का मानना है कि 'लद्दाख के आर्य' (Aryans of Ladakh) या 'ब्रोकपास' (Brokpas) सिकंदर (Alexander) की सेना का हिस्सा थे और 2,000 साल पहले इस क्षेत्र में आए थे।**
- **इस जनजाति के लोग लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी लेह से 163 किमी. दक्षिण पश्चिम में स्थित लेह और करगिल ज़िलों के धा (Dha), हानू (Hanu), दारचिक (Darchik) और गारकोन गाँवों में निवास करते हैं। इन गाँवों को आर्य घाटी कहा जाता है।**
- **तेज़ी से हो रहे आधुनिकीकरण, प्रवास और धर्मांतरण के कारण इन जनजातियों की समृद्ध विरासत खतरे में है।**
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।**

स्वास्थ्य (Health)

विश्व कुष्ठ दिवस

- 27 जनवरी, 2019 को पूरे विश्व में 'विश्व कुष्ठ दिवस' (World Leprosy Day) मनाया गया। यह दिवस हर साल जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है।
- इस वर्ष हेतु इसकी थीम 'भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना' (Ending Discrimination, Stigma and Prejudice) है।
- अक्सर देखा जाता है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों को किसी-न-किसी रूप में कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से आधे अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं।
- कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium Leprae) के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग (Chronic Infectious Disease) है।
- इस रोग की वज़ह से त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुँचता है।
- माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक का नाम डॉ. आर्मोर हैन्सेन है। इसलिये इस रोग को हैन्सेन का रोग के रूप में भी जाना जाता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मल्टीड्रग थेरेपी (Multidrug Therapy- MDT) के द्वारा कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार किया जा सकता है।

स्वाइन फ्लू (Swine Flu)

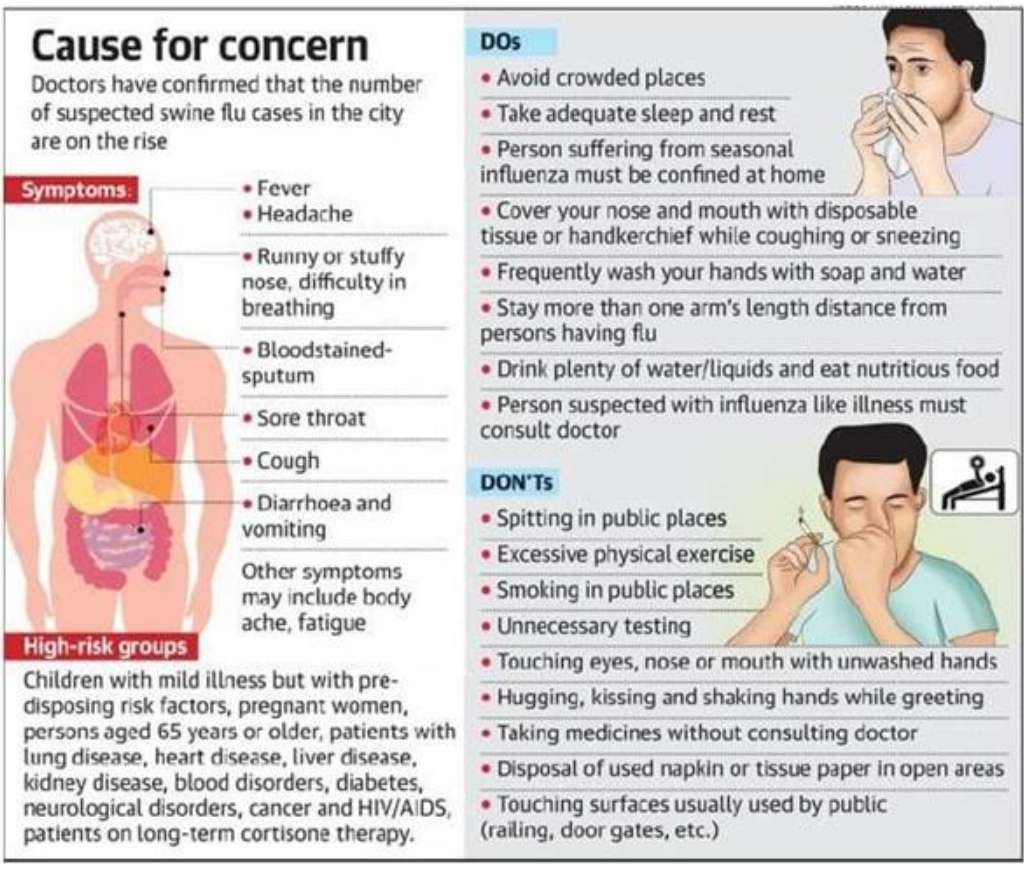

- एक बार फिर देश भर से स्वाइन फ्लू के संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं और यह संक्रमण तेज़ी से फ़ैल रहा है।
- यह H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है, यह सूअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है, जो सूअरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों तक फैल जाते हैं।
- H1N1 एक प्रकार से श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनता है जो कि बहुत संक्रामक होता है।
- H1N1 संक्रमण को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अतीत में यह उन्हीं लोगों को होता था जो सूअरों के सीधे संपर्क में आते थे।
- H1N1 की तीन श्रेणियाँ हैं - A, B और C
- A और B श्रेणियों को घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि श्रेणी C में तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लक्षण और परिणाम बेहद गंभीर होते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है।

- स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा टाइप ए वायरस का ही दूसरा नाम है जो सूअरों (स्वाइन) को प्रभावित करता है। हालाँकि स्वाइन फ्लू आमतौर पर मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन 2009-2010 में इसने एक वैश्विक प्रकोप (महामारी) का रूप धारण कर लिया था, तब 40 वर्षों से अधिक समय के बाद फ्लू के रूप में कोई महामारी पूरी दुनिया में फैली थी।

ई-औषधि पोर्टल (e-AUSHADHI portal)

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिये ई-औषधि (e-AUSHADHI) नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है।

- ई-औषधि पोर्टल का लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना, सूचना प्रबंधन सुविधा में सुधार लाना, डेटा के इस्तेमाल में सुधार लाना और उत्तरदायित्व बढ़ाना है।
- इस पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की प्रक्रिया तथा समय-सीमा के बारे में प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में SMS और ई-मेल के ज़रिये जानकारी दी जाएगी।
- नया ई-पोर्टल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव (Automated Drug Help Initiative) के लिये एक मूल आधार है।
- यह पोर्टल लाइसेंस प्रदाता अधिकारी, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिये मददगार होने के साथ-साथ लाइसेंसशुदा निर्माताओं तथा उनके उत्पादों, रद्द की गई और नकली औषधियों के बारे में जानकारी, शिकायतों के लिये संबंधित अधिकारी के संपर्क-सूत्र भी तत्काल उपलब्ध कराएगा।

ट्रांस फैटी एसिड पर जागरूकता अभियान

केरल स्वास्थ्य विभाग ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों में **ट्रांस फैटी एसिड (Trans Fatty Acid-TFA)** के हानिकारक प्रभावों पर सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने और ट्रांस फैटी एसिड हेतु निर्धारित वर्तमान वैधानिक सीमाओं को पूरा करने के लिये स्थानीय खाद्य उद्योग को प्रोत्साहित करने की एक कार्य योजना बनाई है।

- इस पहल को विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Indian Food Safety and Standards Authority-FSSAI)** और राज्य खाद्य सुरक्षा विंग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

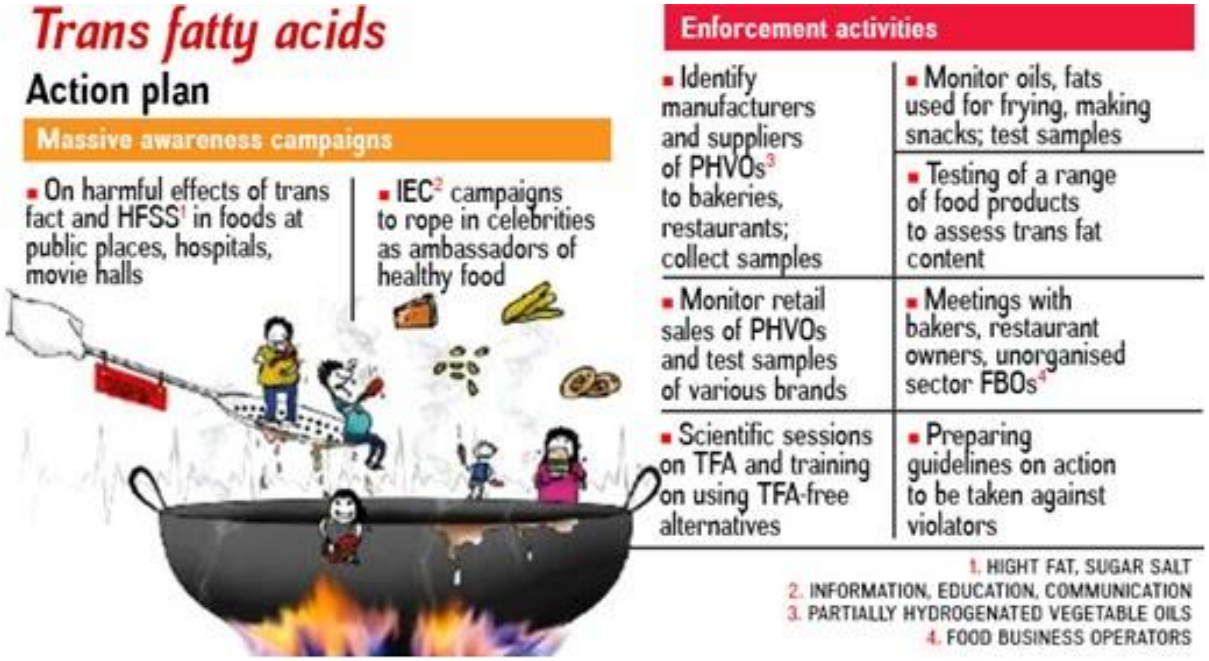

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)

12 फरवरी, 2018 को महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने पोषण अभियान के तहत देश में पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद (National Council on India's Nutrition Challenges) की चौथी बैठक का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की।

- **बैठक के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तथा कार्यकारी समिति की चौथी और 5वीं बैठकों में की गई सिफारिशों के बारे में जानकारी दी।**
- **पोषण (POSHAN) योजना का पूरा नाम 'PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment' है।**
- **इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से की गई थी।**
- **इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में ठिगनापन/स्टंटिंग (Stunting), अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) और जन्म के समय बच्चों के कम वज़न के मामलों में प्रतिवर्ष क्रमश: 2%, 2%, 3% तथा 2% की कमी लाना है।**
- **एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 718 ज़िलों को वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से इस अभियान के तहत शामिल किया जाएगा।**

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान (National Deworming Day)

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का 8वाँ चरण शुरू किया है।

- इस अभियान के तहत करोड़ों बच्चों को कृमि से बचाव हेतु सुरक्षित दवा अलबेंडेजौल (Albendazole) दी जाती है एवं आम लोगों को खुले में शौच करने से कृमि संक्रमण के खतरों तथा साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले 64 फीसदी आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा है।
- अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से आंतों में उत्पन्न होने वाले परजीवी कृमि को खत्म करना है।
- कृमि मुक्ति अभियान 2015 में शुरू किया गया था। अब तक इसके सात चरण पूरे हो चुके हैं एवं यह आठवाँ चरण है। इस चरण में 30 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 1-19 वर्ष की आयु वर्ग के 24.44 करोड़ बच्चों और किशोरों को लक्षित किया गया है।
- कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना** [Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana (PM-JAY)] के बेहतर क्रियान्वयन के लिये **राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (National Health Agency) का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) के रूप में** करने की स्वीकृति दे दी है।

- इस मंज़ूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है तथा इसके स्थान पर **परिवार और कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) से संबद्ध कार्यालय के रूप में** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है।
- निर्णय लेने के वर्तमान **बहुस्तरीय ढाँचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड** (Governing Board) बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिये आवश्यक तेज़ गति से निर्णय लेने में सहायक होगा।
- गवर्निंग बोर्ड का गठन व्यापक स्तर पर किया गया है तथा **इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।**इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में बारी-बारी से राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा।
- **इसके अंतर्गत किसी नए कोष की स्थापना को स्वीकृति नहीं दी गई है।** सूचना प्रौद्योगिकी (IT), मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के लिये पहले से स्वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सक्षम, कारगर तथा पारदर्शी रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से PM-JAY को लागू करने हेतु उत्तरदायी और अधिकृत होगा।

संस्कृति (Culture)

संगराई नृत्य (Sangrai Dance)

संगराई नृत्य मोग (Mog) आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो बंगाली कैलेंडर के चैत्र (अप्रैल में) माह के दौरान मनाए जाने वाले संगराई उत्सव के अवसर पर किया जाता है।

- मोग त्रिपुरा की 19 जनजातियों में से एक है।
- मोग अराकनी वंश (भारत-वर्मा के अराकान क्षेत्र) से संबंधित है जिन्होंने चित्तगोंग पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए त्रिपुरा में प्रवास किया था।
- मोग समुदाय की भाषा को तिब्बत-चीनी परिवार की भाषा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जो असम-बर्मा भाषा खंड से भी जुड़ा हुआ है।

भारत पर्व

- पर्यटन मंत्रालय कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से 26 से 31 जनवरी, 2019 तक लाल किले में एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाने वाले पाँच दिवसीय 'भारत पर्व' का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का ही हिस्सा है।
- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, देश के विविधता पूर्ण सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना और जन-भागीदारी बढ़ाना है।
- एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मद्देनज़र भारत पर्व का आयोजन 2016 से गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
- इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय करता है। इस बार आयोजन के दौरान गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झाँकियों की प्रदर्शनी, सशस्त्र बलों के बैंड का प्रदर्शन, पाक कला, फूड कोर्ट और डीएवीपी द्वारा फोटो प्रदर्शनी पेश की जाएगी।
- भारत पर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिये पर्यटन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (Pakke Paga Hornbill Festival)

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF), राज्य के एकमात्र संरक्षण महोत्सव को 'राज्य उत्सव' घोषित किया।

- हॉर्नबिल [निशि/न्यिशी (Nyishi) भाषा में 'पागा') के नाम पर पाक्के पागा महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था।
- इस उत्सव का पहला संस्करण जनवरी 2015 में अरुणाचल प्रदेश के सिजोसा (Seijosa) में आयोजित किया गया था।
- यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग (East Kameng) ज़िले के सिजोसा के दारलोंग (Darlong) गाँव में आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य

- पाक्के तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय न्यिशी समुदायों एवं अन्य समुदायों द्वारा राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण में निभाई गई भूमिका को लोकप्रिय बनाना।
- अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और वन्यजीव विरासत, विशेष रूप से पक्के/पाक्के टाइगर रिजर्व (Pakke Tiger Reserve) के बारे में शहरी भारतीयों और बाहरी आगंतुकों के बीच रुचि और जागरूकता पैदा करना।

रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो को वर्ष 2020 के लिये **वर्ल्ड कैपिटल ऑफ़ आर्किटेक्चर (World Capital of Architecture)** घोषित किया है।

- पेरिस और मेलबर्न को पीछे छोड़ते हुए रियो डी जेनेरियो पिछले साल नवंबर में यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स (Union of Architects-UIA) द्वारा एक साथ शुरू किये गए कार्यक्रम के तहत यह खिताब हासिल करने वाला पहला शहर है।
- यह शहर जुलाई 2020 में UIA के वैश्विक सम्मेलन (World Congress) की मेज़बानी करेगा। उल्लेखनीय है कि UIA का यह सम्मेलन तीन सालों में एक बार आयोजित होता है।
- यूनेस्को के अनुसार, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का उद्देश्य संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, शहरी नियोजन और वास्तुकला के दृष्टिकोण से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने से संबंधित वार्ता के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना है।
- ब्राज़ील के सबसे पुराने शहरों में से एक रियो डी जेनेरियो आधुनिक और औपनिवेशिक वास्तुकला का मिश्रण है जिसमें विश्व प्रसिद्ध स्थलों जैसे-ईशा मसीह की मूर्ति और म्यूज़ियम ऑफ़ टुमारो (Museum of Tomorrow) आदि समकालीन निर्माण शामिल हैं।

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (United Nation Organisation-UNO) का एक घटक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है।
- संगठन में 195 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।

Union of Architects (UIA)

- इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स (UIA) की स्थापना 28 जून, 1948 को लुसाने (Lausanne), स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) में हुई थी।
- UIA एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे UNESCO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एकमात्र वास्तुशिल्प संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जल्लीकट्टू (Jallikattu)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हर साल जनवरी में पोंगल के समय इस प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। इस पारंपरिक आयोजन में हर साल लोगों के गंभीर रूप से घायल होने, यहाँ तक कि मरने की खबरें भी आती रही हैं।

- जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है।
- जल्लीकट्टू तमिल के दो शब्दों **'जल्ली'** और **'कट्टू'** से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सांड़ के सींग पर सोने या चांदी के बांधे गए सिक्के।
- इस खेल में बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फँसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है, ताकि लोग बैलों के सींगों को पकड़कर उन्हें काबू में करें।
- कथित तौर पर पराक्रम से जुड़े इस खेल में विजेताओं को नकद इनाम वगैरह भी देने की परंपरा है।

- उल्लेखनीय है कि इस खेल के आरंभिक दिनों में एक बैल को नियंत्रण में लेने का प्रयास एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक जल्लीकट्टू खेल के दौरान बैलों को भड़काने के लिये उन्हें शराब पिलाने से लेकर उनकी आँखों में मिर्च तक डाली जाती है और उनकी पूंछों को मरोड़ा भी जाता है, ताकि वे तेज़ दौड़ें।
- पिछले कुछ सालों को छोड़ दें तो तमिलनाडु में यह खेल बिना किसी विरोध के आयोजित होता रहा है।

'सांझी-मुझ में कलाकार' (SANJHI -MUJH MEIN KALAKAR)

"सांझी-मुझ में कलाकार" संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi-SNA) का एक वेब अभियान है जिसके दूसरे चरण की शुरुआत SNA द्वारा की जाएगी।

- यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage-ICH) तथा सीधे जन भागीदारी द्वारा विविध सांस्कृतिक विरासतों को विकसित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक पहल है।
- यह एक विशिष्ट प्रतिभा खोज कार्यक्रम है जिसमें भागीदार संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, लोक और जनजातीय कलाओं, पाक कौशल, चित्रकला और मूर्ति कला जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
- इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत नवंबर 2018 में की गई थी।

संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi)

- संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय एकेडमी है।
- यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है।
- इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के 31 मई, 1952 के प्रस्ताव के ज़रिये किया गया था और भारत के गज़ट में इसे जून 1952 में अधिसूचित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डॉ. पी. वी. राजमन्नार थे।
- यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न यूनेस्को (UNESCO) सम्मेलनों से संबंधित मामलों को समन्वित करने के लिये भारत की सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों का प्रचार एवं प्रसार करती है।

अगस्त्याकूर्दम चोटी

हाल ही में सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर (Ayyappa Temple) में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के बाद केरल के ही एक अन्य स्थान पर लैंगिग भेदभाव को मिटाने वाला कदम उठाया गया है।

- राज्य की दूसरी सबसे ऊँची चोटी, अगस्त्याकूर्दम (Agasthyarkoodam) की ओर जाने वाले दुर्गम मार्ग को पहली बार महिलाओं के लिये खोला गया है।

पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनई मुड़ी (Anai Mudi) है जिसकी ऊँचाई 2,695 मीटर है।

- रक्षा प्रवक्ता, के. धन्या सानल (K Dhanya Sanal) अगस्त्याकूर्दम चोटी की यात्रा करने वाली पहली महिला बन गई है।
- केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वन विभाग ने महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाया है।
- पहाड़ी की तलहटी पर रहने वाली स्थानीय कानी जनजाति इस फैसले का विरोध करती रही है। उनके अनुसार, यह पर्वत श्रृंखला 'अगस्त्य मुनि' का पवित्र निवास स्थान है।
- अगस्त्याकूर्दम चोटी केरल के अगस्त्याकूर्दम जीवमंडल रिज़र्व (Agasthymala Biosphere Reserve) में नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य (Neyyar Wildlife Sanctuary) में स्थित है।
- अगस्त्याकूर्दम जीवमंडल रिज़र्व 2016 में यूनेस्को द्वारा **'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ़ बायोस्फीयर रिज़र्व'** (World Network of Biosphere Reserves) में जोड़े गए 20 नए स्थलों में से एक है।

ताज व्यू गार्डन (Taj View Garden)

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने आगरा के किले और ताजमहल के बीच **ताज कॉरिडोर क्षेत्र** में **'ताज व्यू गार्डन'** की नींव रखी।

- इस गार्डन के निर्माण का उद्देश्य बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करके ताजमहल के चारों ओर हरियाली को बढ़ावा देना है। इससे न केवल ताजमहल के आस-पास के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि यह आगंतुकों को एक मनोरम दृश्य भी प्रदान करेगा।
- ताज व्यू गार्डन को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा मुगलकालीन चारबाग उद्यान की तर्ज़ पर विकसित किया जा रहा है।
- चारबाग शैली उद्यान स्थापत्य की एक फ़ारसी शैली है जिसमें एक वर्गाकार बाग को चार छोटे भागों में, चार पैदल पथों या बहते पानी द्वारा चार छोटे भागों में बाँटा जाता है।
- इस तरह की उद्यान शैली ईरान और भारत सहित संपूर्ण पश्चिमी और दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती है।
- भारत में हुमायूँ के मकबरे (दिल्ली) और ताज महल (आगरा) का निर्माण चारबाग शैली में किया गया है।

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम (Cultural Heritage Youth Leadership Programme-CHYLP)

केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय ने युवाओं में भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिये सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम(CHYLP) हेतु सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र(CCRT) को वर्ष 2018-19 के दौरान 10 लाख रुपए आवंटित किये।

कार्यक्रम के बारे में

- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव को बढ़ाने और स्कूली बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता के प्रोत्साहन के उद्देश्य से 19 नवंबर, 2011 को सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे अलाभान्वित बच्चों पर खास ध्यान देना है।

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र(CCRT)

- सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है, जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है।
- इसकी स्थापना मई 1979 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय तथा डॉ. कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी।
- यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है।
- इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके तीन क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद तथा पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में स्थित हैं।

बौद्ध सर्किट के अंतर्गत पाँच नई परियोजनाओं को मंज़ूरी

बौद्ध सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिये चिह्नित विषयगत (थीम आधारित) सर्किटों में से एक है। मंत्रालय ने इस सर्किट के तहत 361.97 करोड़ की 5 नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

ये पाँच परियोजनाएँ हैं-

1. सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध सर्किट का विकास (मध्य प्रदेश)
2. श्रावस्ती, कुशीनगर, और कपिलवस्तु में बौद्ध सर्किट का विकास (उत्तर प्रदेश)
3. बोधगया के पश्चिमी तरफ माया सरोवर के निकट कन्वेंशन सेंटर का निर्माण (बिहार)

4. जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भरूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेहसाणा बौद्ध सर्किट का विकास (गुजरात)
5. सलीहुंडम-थोटलाकोंडा-बाविकोन्डा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू बौद्ध सर्किट का विकास (आंध्र प्रदेश)

स्वदेश दर्शन योजना

- स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर खास विशेषता वाले सर्किटों का विकास करना है।
- इस योजना के तहत सरकार जहाँ एक ओर पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएँ देने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण ढाँचागत विकास पर ज़ोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर रही है।
- इस योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी।
- इस योजना के तहत जिन विषयगत आधारों पर सर्किटों का विकास किया जाता है, उनके नाम हैं- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन-जीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट एवं धरोहर सर्किट।

महामस्तकाभिषेक महोत्सव

हाल ही में श्रवणबेलगोला स्थित भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का अनावरण कर राष्ट्रपति ने महामस्तकाभिषेक महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 9-18 फरवरी, 2019 तक मनाया जाएगा।

- महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अब तक का यह चौथा महामस्तकाभिषेक है इससे पहले यह वर्ष 1982, 1995, 2007 में मनाया गया।
- भगवान बाहुबली पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के पुत्र थे।
- जैन मान्यताओं के अनुसार, बाहुबली ने निरंतर लंबी अवधि तक ध्यान में रहकर सांसारिक विषय-विकारों से मुक्ति प्राप्त की थी एवं मोक्ष भी सबसे पहले बाहुबली को ही प्राप्त हुआ था।

गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा का अनावरण

- ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 8 फ़रवरी को गजपति ज़िले के जिरांग क्षेत्र में गुरु पद्मसंभव की 19 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु पद्मसंभव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वे ओडिशा में पैदा हुए, वहीं पले-बढ़े और तत्पश्चात तिब्बत चले गए। इन्हे दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है।
- पत्थर की यह 29 टन वजनी प्रतिमा पद्मसंभव महावीर मठ के पास स्थित पद्म सरोवर के मध्य में है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मठ है। इसका उद्घाटन 2010 में दलाई लामा द्वारा किया गया था। यह मूर्ति प्रख्यात मूर्तिकार पद्मश्री प्रभाकर मोहराना द्वारा बनाई गई है।
- मूर्ति अनावरण समारोह में अपने धार्मिक और प्रशासनिक नेताओं के साथ तिब्बत वासियों का एक बड़ा समूह उपस्थित था।

स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत चार नई परियोजनाएँ

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन ढाँचागत विकास योजनाओं **'स्वदेश दर्शन'** और **'प्रसाद'** के तहत मेघालय, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 190.46 करोड़ रुपए की लगात वाली चार नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

स्वदेश दर्शन के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ-

- स्वदेश दर्शन योजना के उत्तर-पूर्व सर्किट के तहत मेघालय की पश्चिम खासी पहाड़ियों (West Khasi Hills) के विकास [नॉन्गख्लाव (Nongkhlaw)-क्रेम टिरोट (Krem Tirot)-खुदोई (Khudoi) और कोहमांग फॉल्स (Kohmang Falls)-खरी (Khri) नदी-मावथडराइशन (Mawthadraishan), शिलांग (Shillong)], जयंतिया पहाड़ी (क्रांग सूरी फॉल्स (Krang Suri Falls)-शिरमांग (Shyrmang)-लुक्सी (looksi)], गारो पहाड़ी (नॉकरेक रिज़र्व (Nokrek Reserve), कट्टा बील (Katta Beel), सिजू गुफा (Siju Caves)] में 84.95 करोड़ रुपए की परियोजना को मंज़ूरी दी है।
- ये परियोजनाएँ मेघालय की कम चर्चित जगहों के विकास पर केंद्रित है।
- स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक सर्किट के तहत गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपाटन मंदिर, बलरामपुर और वात्वासनी मंदिर (डुमरियागंज) के विकास के लिये 21.16 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दी है।

प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत योजनाएँ

- प्रसाद योजना के तहत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में **'गोवर्धन के विकास'** के लिये 39.74 करोड़ रुपए की परियोजना को मंज़ूरी दी है। इसके तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, कुसुम सरोवर, चंद्रा सरोवर और मानसी गंगा का विकास किया जाएगा।
- प्रसाद योजना के तहत 44.59 करोड़ रुपए की **'सोमनाथ-फेज-2** में तीर्थाटन सुविधाओं का विकास' नामक परियोजना को मंज़ूरी दी गई है।

पृष्ठभूमि

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन स्थलों के **थीम आधारित एकीकृत विकास** के लिये **'स्वदेश दर्शन योजना'** की शुरूआत की और **तीर्थस्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिये 'प्रसाद' (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive-PRASHAD)** परियोजना की शुरूआत की है।

केरल में आध्यात्मिक सर्किट (Spiritual Circuit in Kerala)

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (Union Ministry of Tourism) ने केरल में 14 ज़िलों के 133 धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले आध्यात्मिक सर्किट के विकास को **स्वदेश दर्शन** (Swadesh Darshan) योजना के तहत मंज़ूरी दी है।

- योजना में शामिल किये गए धार्मिक स्थलों का चयन उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व के आधार पर किया गया है।
- योजना के अंतर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों में सामुदायिक हॉल, अन्नधान मंडपम (Annadhana Mandapam), बहुउद्देशीय हॉल, शौचालय, कैफेटेरिया, पार्किंग सुविधाएँ, रास्ते, रोशनी,पहचान सूचकों (signages), डस्टबिन आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

कंबाला त्योहार/उत्सव (Kambala Festival)

कंबाला त्योहार दक्षिण-पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक दो दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। जिसका आयोजन सामान्यत: नवंबर से मार्च महीने के बीच किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस उत्सव में किसान दो भैंसा को हल से बाँधकर पानी से भरे क्षेत्र में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और विजयी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है।

- एक मान्यता के अनुसार, यह त्योहार कर्नाटक के कृषक समुदाय द्वारा प्रारंभ किया गया था जो भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। इस त्योहार के माध्यम से अच्छी फसल प्राप्त करने के लिये देवताओं को खुश किया जाता था।
- यह त्योहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्योहार जैसा है, बस अंतर इतना है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इस त्योहार की निंदा कर इसे पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार बताते हुए चिंता जाहिर की, जिस गति से किसान और भैंस दौड़ते हैं उससे उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आ सकती हैं।
- वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमों के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाला और जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
- 3 जुलाई, 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश, 2017 [11] की घोषणा को मंज़ूरी दे दी और कर्नाटक में कंबाला उत्सव को वैध कर दिया गया है।

विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day)

- हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day) मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक दशक पहले 10 जनवरी, 2006 को की थी।

- विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारत के दूतावासों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।

आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भित्तिचित्र स्थल

हाल ही में आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े भित्तिचित्र स्थल का अनावरण किया गया है।

- **इस भित्तिचित्र को योगी वेमाना विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्त्व विभाग के साथ शैक्षणिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे एक पुरातत्त्वविद् यादव रघु द्वारा खोजा गया है।**
- **इस स्थल पर लगभग 80 भित्तिचित्र हैं जो कुरनूल ज़िले के असपारी शहर के निकट मेकाला बेन्ची में स्थित है।**
- **200 भित्तिचित्रों वाला कंदनाथी (Kandanathi) स्थल भी कुरनूल ज़िले में ही है जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा भित्तिचित्र स्थल है।**

विविध (Miscellaneous)

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018

5 दिसंबर, 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी जिसका वितरण 29 जनवरी, 2019 को किया गया।

- इसके अंतर्गत **हिन्दी में चित्रा मुद्गल, अंग्रेज़ी में अनीस सलीम, उर्दू में रहमान अब्बास, संस्कृत में रमाकांत शुक्ल और पंजाबी में मोहनजीत** सहित कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इन पुरस्कारों की अनुशंसा अकादमी के अध्यक्ष डॉ चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी मंडल की बैठक में 24 भाषाओं की निर्णायक समिति द्वारा की गई थी।
- इस बार सात कविता-संग्रहों, छह उपन्यासों, छह कहानी संग्रहों, तीन आलोचनाओं और दो निबंध संग्रहों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है।

'ट्रेन 18' अब 'वंदे भारत एक्सप्रेस'

हाल ही में **ट्रेन 18** का नाम बदलकर '**वंदे भारत एक्सप्रेस**' करने की घोषणा की गई है।

- सुरक्षा मानकों के साथ-साथ अन्य परीक्षणों को पास कर लेने के बाद देश में निर्मित सेमी-हाईस्पीड ट्रेन 18 यात्रियों की सेवा के लिये अब तैयार है।

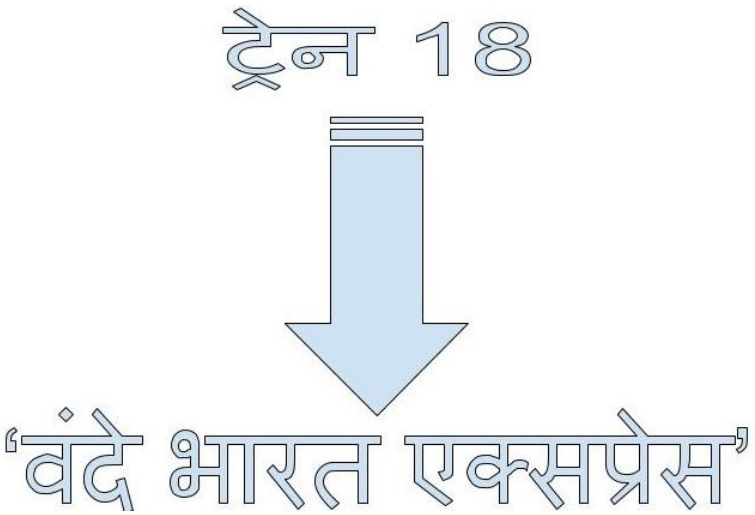

- **'वंदे भारत एक्सप्रेस'** या ट्रेन 18 नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 755 किलोमीटर की दूरी महज़ आठ घंटे में तय करेगी। नई दिल्ली से चलकर यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज में रुकने के बाद वाराणसी पहुँचेगी।
- यह दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन होगी। अभी तक सबसे तेज़ ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी 11 घंटे 30 मिनट में तय करती है।

हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, 2018- नारी शक्ति

हाल ही में ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरीज़ ने वर्ष 2018 का **'हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर'** के रूप में **'नारी शक्ति'** को चुना है।

- ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरीज़ का इस वर्ष का हिंदी शब्द, एक ऐसा शब्द या अभिव्यक्ति है, जो बीते हुए वर्ष की प्रकृति, मिजाज़, माहौल और मानसिकता को व्यक्त कर सकता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में नारी की बढ़ती सक्रियता ही नारी शक्ति है। यह शब्द संस्कृत से जन्मा है। नारी का अर्थ है 'महिला' और 'शक्ति' उसकी असीम ऊर्जा को व्यक्त करता है।
- ऑक्सफोर्ड ने 2017 में 'आधार' शब्द चुना था। आक्सफोर्ड ने यह पहल 2017 से शुरू की थी।

- वर्ष 2018 के दौरान महिलाओं को लेकर कई कानूनों में बदलाव और सुधार किये गए इसके साथ ही #मीटू जैसे आंदोलन भी चर्चा में रहे।
- देश भर में इस दौरान महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकार पर काफी बहस हुई। यही वज़ह है कि इस शब्द पर ज़ोर दिया गया। नारी शक्ति शब्द पर मार्च 2018 में सबसे ज्यादा ज़ोर दिया गया था।

राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day)

24 जनवरी को पूरे भारत में **राष्ट्रीय बालिका दिवस** के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि **अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस** हर साल **11 अक्तूबर** को मनाया जाता है।

- राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 की थीम **'उज्ज्वल कल के लिये लड़कियों का सशक्तीकरण' (Empowering Girls for a Brighter Tomorrow)** है।
- इस दिवस को मनाने की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली विषमताओं को उजागर करना, बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा के महत्त्व, स्वास्थ्य और पोषण, गिरते हुए बाल लिंग अनुपात (Child Sex Ratio-CSR) सहित कई विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देना और बालिकाओं के आस-पास सार्थक वातावरण बनाना है।

सुभाष चंद्र बोस

23 जनवरी, 2019 को **सुभाष चंद्र बोस** की 122वीं जयंती मनाई गई।

- इस अवसर पर लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय (Subhas Chandra Bose Museum) का उद्घाटन किया गया तथा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा भी की गई।

सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय

- इस विशेष संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी, तलवार, पदक, बैच और आज़ाद हिंद फौज की वर्दी आदि शामिल हैं।
- इस संग्रहालय में आजाद हिंद फौज के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

- सभी भारतीय नागरिक और संगठन जिन्होंने आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों यथा रोकथाम, तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास, शोध या पूर्व चेतावनी में विशिष्ट योगदान दिया है, वे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के योग्य हैं।
- इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए की नकद धनराशि तथा एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- वर्ष 2019 के लिये गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force-NDRF) की आठवीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 (World University Ranking 2019)

हाल ही में लंदन स्थित वैश्विक संगठन टाइम्स हायर एजुकेशन ने इमर्जिंग इकोनॉमीज़ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 (Emerging Economies University Rankings 2019) जारी की।

- टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education) द्वारा जारी इस रैंकिंग में 43 देशों के 450 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
- इस रैंकिंग में भारत के 49 संस्थानों को स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस रैंकिंग में भारत के 42 संस्थानों को स्थान मिला था।

- इस सूची में चीन के 75 संस्थान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष 5 में से 4 स्थानों पर चीन के संस्थानों को स्थान मिला है।

शीर्ष 100 में शामिल भारतीय संस्थान

संस्थान का नाम	रैंकिंग
IISC बंगलूरू	14
IIT बॉम्बे	27
IIT रुड़की	35
IIT कानपुर	46

IIT खड़गपुर	55
IIT इंदौर	61
JSS एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च	64
IIT दिल्ली	66
IIT मद्रास	75
सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे	93

गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize)

सरकार ने चार वर्षों 2015, 2016, 2017 और 2018 के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी है।

- वर्ष 2015,2016,2017 और 2018 के लिये गांधी शांति पुरस्कार से निम्नलिखित को सम्मानित किया गया है-

वर्ष	सम्मानित संस्था/व्यक्ति	कार्य
2015	विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी	ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों का विकास
2016	अक्षयपात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल	अक्षयपात्र को भारत के लाखों बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने तथा सुलभ इंटरनेशनल को सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिये
2017	एकल अभियान ट्रस्ट	आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण सशक्तीकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता
2018	योहेई ससाकावा (YoheiSasakawa), विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत	भारत और दुनिया भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन में उनके योगदान के लिये

पृष्ठभूमि

- महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
- इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि, प्रशस्ति-पत्र, एक पट्टिका के साथ-साथ एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा की वस्तु दी जाती है।
- यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में योगदान करने वाले लोगों और संस्थानों को दिया जाता है।

मोबाइल एप 'आरडीपी इंडिया 2019'

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 'डिजिटल इंडिया' अभियान के अनुपालन में एक नई पहल की शुरुआत की है।

- गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने एक मोबाइल एप 'आरडीपी इंडिया 2019' जारी किया। इसका उद्देश्य गणतंत्र दिवस समारोह की रूपरेखा को राजपथ पर मौजूद दर्शकों के अलावा दुनिया भर के आम लोगों को उपलब्ध कराना था।
- इस एप में नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड की सूचनाएँ मौजूद थीं, जिसमें परेड के क्रम, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत झांकियों का विवरण, बच्चों के सांस्कृतिक प्रदर्शनों, फ्लाई-पास्ट तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेताओं के नामों की जानकारी शामिल थी।
- परेड में उपस्थित सभी दर्शकों के लिये यह एप काफी सूचनात्मक रहा और इसकी हर तरफ प्रशंसा की गई। इस एप में परेड की लाइव-स्ट्रीमिंग का भी प्रावधान था।
- एप को डाउनलोड करके परेड देखने के साथ-साथ आयोजन के बारे में सूचनाएँ अब भी प्राप्त की जा सकती हैं।

फिलिप कोटलर प्रेसीडेंशिअल अवार्ड

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को **पहला फिलिप कोटलर प्रेज़िडेंशियल पुरस्कार** (Philip Kotler Presidential award) प्रदान किया गया।

- यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिये प्रदान किया गया है।
- यह पुरस्कार तीन आधार रेखाओं- पीपुल (People), प्रॉफिट (Profit) और प्लैनेट (Planet) पर केंद्रित है, जो प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा।
- यह अवार्ड प्रोफेसर फिलिप कोटलर के नाम से दिया गया जो 'नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (Northwestern University, Kellogg School of Management) के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं।

राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)

समाज सुधारक, दर्शनिक और सुप्रसिद्ध विचारक स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन के अवसर पर अर्थात् 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- **संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation Organisation)** के निर्णयानुसार **वर्ष 1985 को 'अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष'** घोषित किये जाने के बाद भारत सरकार ने स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता में हुआ था तथा इनका **वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त** था।
- ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे।
- विवेकानंद ने बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में **रामकृष्ण मिशन** की स्थापना की।

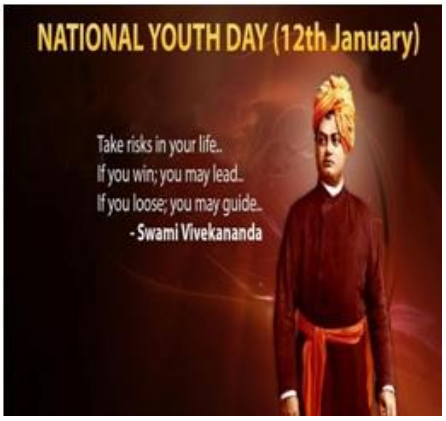

भारत में विवेकानंद की सबसे ऊँची प्रतिमा

- स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रांची के **'बड़ा तालाब'** में विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
- यह प्रतिमा विवेकानंद की देश में सबसे ऊँची प्रतिमा (33 फीट) है। इस प्रतिमा की स्थापना के बाद डेढ़ सौ साल पुराने 'बड़ा तालाब' को भी विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाएगा।
- विवेकानंद की इस प्रतिमा में छह टन काँसे और दो टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है।

सावित्रीबाई फुले

3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 187वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- यूँ तो उनको कई क्षेत्रों में उपलब्धियाँ प्राप्त थीं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से मनुवादी संस्कृति को चुनौती देने के लिये जाना जाता है।
- सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र में सतारा ज़िले के नायगांव में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा राव फुले से हुआ था।
- ज्योतिबा ने सावित्रीबाई फुले को घर पर ही पढ़ाया और बाद में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर पुणे के महारवाड़ा में सगुनाबाई (एक क्रांतिकारी नारीवादी) के साथ लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया।
- 1850 के दशक में, फुले दंपति ने दो शैक्षिक ट्रस्टों- नेटिव फीमेल स्कूल (Native Female School), पुणे और The Society for Promoting the Education of Mahars, Mangs and Etceteras की शुरुआत की।
- सावित्रीबाई एक उग्र लेखिका और कवयित्री भी थीं। उन्होंने 1854 में काव्य फुले (Kavya Phule) और 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर (Bavan Kashi Subodh Ratnakar) को प्रकाशित किया। अपनी कविता गो, गेट एजुकेशन (Go, Get Education) के ज़रिये उन्होंने उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की ज़ंजीरों से मुक्त होने का आग्रह किया।

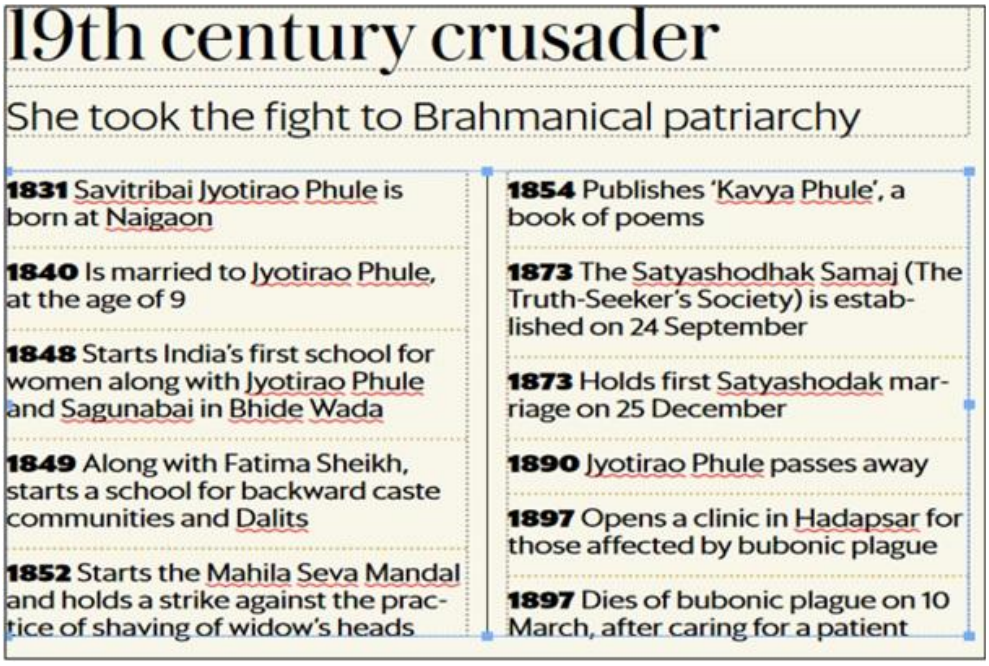

19th century crusader

She took the fight to Brahmanical patriarchy

1831 Savitribai Jyotirao Phule is born at Naigaon

1840 Is married to Jyotirao Phule, at the age of 9

1848 Starts India's first school for women along with Jyotirao Phule and Sagunabai in Bhide Wada

1849 Along with Fatima Sheikh, starts a school for backward caste communities and Dalits

1852 Starts the Mahila Seva Mandal and holds a strike against the practice of shaving of widow's heads

1854 Publishes 'Kavya Phule', a book of poems

1873 The Satyashodhak Samaj (The Truth-Seeker's Society) is established on 24 September

1873 Holds first Satyashodak marriage on 25 December

1890 Jyotirao Phule passes away

1897 Opens a clinic in Hadapsar for those affected by bubonic plague

1897 Dies of bubonic plague on 10 March, after caring for a patient

70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स (70 points grading index)

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स (70-point grading index) लॉन्च किया।

- **इसके तहत स्कूलों की शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन के लिये 70 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाएगा।**
- **70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स की सहायता से राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों अथवा कमज़ोर पक्षों का आकलन किया जाएगा ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा सकें।**
- **इस पहल द्वारा राज्यों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि वे किन मानकों पर पिछड़ रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है।**
- **इस ग्रेडिंग इंडेक्स के कुछ महत्त्वपूर्ण संकेतकों में अध्यापकों की रिक्तियाँ, नेतृत्त्व के स्तर (Leadership Position) पर सीधी नियुक्ति, स्कूल की आधारिक संरचना आदि शामिल हैं।**
- **इस सूचकांक के अंतर्गत 1000 अंक (Point) होंगे, प्रत्येक मानक के लिये 10-20 अंक रखे जाएंगे।**
- **राज्यों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिये किये जा रहे कार्यों हेतु निधि की व्यवस्था भी की जाएगी।**
- **इस प्रणाली से प्रत्येक राज्य के स्कूली शिक्षा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी साथ ही राज्यों को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का अवसर प्राप्त होगा।**

सी विजिल 2019 (Sea Vigil 2019)

समुद्र के रास्ते होने वाले हमले के खिलाफ देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के लिये के भारतीय नौसेना का दो दिवसीय रक्षा अभ्यास 22 जनवरी, 2019 को शुरू हुआ।

- **इस अभ्यास को 'सी विजिल 2019' नाम दिया गया है और इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला यह पहला अभ्यास है।**
- **यह सुरक्षा अभ्यास तटीय रक्षा के कमांडर इन चीफ व दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि के निरीक्षण में आयोजित किया जा रहा है और इसकी निगरानी संयुक्त अभियान केंद्र, कोच्चि कर रहा है।**
- **इस दो दिवसीय अभ्यास के दौरान पूरे देश के तटीय और विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) को कवर किया जाएगा।**
- **इस अभ्यास का उद्देश्य मुंबई आतंकवादी हमले के बाद से किये गए उपायों की प्रभावकारिता को व्यापक और समग्र रूप से सुदृढ करना करना है।**
- **इस वृहद् अभ्यास का मुख्य लक्ष्य तटीय क्षेत्रों की समग्र सुरक्षा और समुद्री मार्ग के माध्यम से घुसपैठ द्वारा एक हमले को विफल करने में उनकी तैयारी का परीक्षण करना है।**
- **उल्लेखनीय है की पिछले दस वर्षों में तटरक्षक बल ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर 347 ऑपरेशन और 180 तटीय सुरक्षा अभ्यास किये हैं, जिनमें तटीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करने के लिये आयोजित किया जाने वाला एक अर्द्धवार्षिक अभ्यास सागर कवच (Sagar Kavach) भी शामिल है।**